

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 जुलाई, 1974

खण्ड-2 अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय-सूची

सोमवार, 11 जुलाई, 1974

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4) 1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(4) 27
गैर सरकारी संकल्प— जिला महेन्द्रगढ के सूखे तथा पिछडे क्षेत्रो में पीने के (मीठे) पानी की नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई के लिए तुरंत आव यक प्रबंध किए जाने के संबंध में	(4) 33
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण— चौधरी चांद राम द्वारा	(4) 62

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 11 जुलाई , 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन

सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09:30 बजे हुई। अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Fertilizer

***799. Ch. Ram Lal Wadhwa.** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total number of bags of fertilizr received in the State during the period from 1st January, 1973 to date; and

(b) the districtwise number of bags distributed out of those referred to in part(a) above during the said period?

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) खाद की 50 किलोग्राम की 65,57,890 बोरियां (1-1-73 से 30-4-74 तक)

(बी) खाद की बोरियों की जिलेवार बांट निम्न प्रकार से है।

जिले का नाम	खाद की बारियों की संख्या
अम्बाला	8,76,210
कुरुक्षेत्र	12,14,200
करनाल	13,55,810
श्रोहतक	3,93,420
सेनीपत	3,42,470
जेंद	3,06,500
भिवानी	1,92,520
थहसार	6,15,920
सिरसा (जो न)	5,17,630
गुडगांव	5,65,880
महेन्द्रगढ	1,77,330
कुल:	65,57,890

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जितनी खाद आ रह है क्या वह हरियाणा के लिए पर्याप्त है? अगर नही तो उसके लिए सरकार क्या साधन जुटाने जा रही है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि रबी के लिए हमारी स्टेट की जो डिमांड है वह सात लाख टन और खरीफ के लिए हमें चाहिए 4 लाख टन। पिछले साल हमें जो रबी के लिए खाद मिली वह थी साढ़े तीन लाख टन और खरीफ के लिए मिली वह है डेढ़ लाख टन। तो हमें खाद हमारी डिमांड के मुताबिक पुरी नहीं मिलती। खाद पीछे से ही कम आती है इसलिए भारत सरकार हमारी डिमांड से हमें कुछ कम देती है।

श्री औम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कौन-कौन किस्म और कितनी बोरियां जिलावार गईं?

चौधरी भजन लाल: मांगी गई सूचना इस प्रकार है:—

जिला	यूरिया	डी0ए0पी0	किसान खाद 26	किसान खाद 25	अमोनियम सल्फेट	सुपर फास्फेट	म्यूरैड आर्फीटा I	कुल
अम्बाला	4,54,550	83,320	29,060	2,36,740	7,660	42,880	22,000	8,76,210
कुरुक्षेत्र	8,87,700	1,76,680	2,180	95,760	11,400	24,640	15,840	12,14,200
करनाल	8,32,370	1,79,900	8,400	2,36,700	9,340	63,740	25,360	13,55,810
रोहतक	1,13,640	6,640	21,000	2,46,500	—	5,640	—	3,97,420
सोनीपत	1,64,010	31,140	15,260	1,28,340	—	3,280	440	3,42,470
जींद	1,02,040	12,260	22,420	1,65,680	—	3,660	440	3,06,500
भिवानी	1,19,380	880	5,440	66,820	—	—	—	1,92,520
हिसार	2,64,740	27,160	26,200	2,66,740	—	24,700	6,380	6,15,920
सिरसा	3,10,870	48,860	25,480	1,23,620	—	8,800	—	5,17,630

गुडगांव	2,44,760	25,400	37,080	2,50,640	—	7,600	400	5,65,880
महेन्द्रगढ	58,830	1,800	3,280	1,07,620	—	1,800	—	1,77,330
कुल:	35,52,890	5,94,040	1,99,800	19,25,160	28,400	1,86,740	70,860	65,57,890

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में यह खाद की सप्लाई और डिमांड का फर्क है इसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रहा है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि काउ डंग इज् गुड तो खास करके जो गोबर की खाद है उसके लिए क्या कर रहे हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जिस समय गांधी जी ने कहा था तो उस समय इतनी प्रोडक्शन भी नहीं थी। उस वक्त में और आज में बहुत अंतर है। अंतर यहाँ है कि जो हमारी हाई इल्लिडिंग वैराइटीज है उसमें अगर इस किस्म की खाद न हो तो इतनी पैदावार नहीं हो सकती। इसके अलावा हम गोबर गैस प्लांट लगाने जा रहे हैं ताकि फर्टीलाइज़र की जितनी डिमांड है उसको पूरा कर सकें। इसके अलावा हरी खाद भी बनाने जा रहे हैं और किसानों को खाद के बीज पर सबसिडी भी देते हैं ताकि किसान उससे भी अपनी पैदावार बढ़ा सकें।

चौधरी मेहर चंद: क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि खाद की कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी खपत उतनी ही है जितनी पहले होती रही है तो इसके लिए कोई तजवीज है कि खाद पूरी मिल सके?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, खाद की कीमत बढ़ने के बाद थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है। पिछले साल जून के महीने

में खाद साढ़े नौ हजार टन लगी थी और इस साल जून के महीने में करीब छः सवा छः हजार टन लगी है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेगें कि यह जो फर्डीलाईज़र के भाव डबल हो गए हैं तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किसानों को सबसीडाइज्ड रेट्स पर खाद मुहैया की जाए?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि सबसीडाइज्ड करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रोपोजल नहीं है। अलबत्ता हम यह जरूर करने जा रहे हैं कि जहां आपने खाद के भाव महंगे किए हैं वहां अनाज के भावों पर भी गौर करें ताकि किसान का उसी अनुपात से अनाज का भाव बढ़ाया जाए।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगें कि जैसा कि भारत सरकार की तरफ से हमें एक करोड़ तीन लाख रुपया मिला है किसानों के इन्सैंटिव के लिए, डिमांड में इन्होंने कहा था कि एक करोड़ रुपया सबसीडाइज़ करेगें अब इन्होंने कहा है कि सबसीडाइज़ वाली कोई बात ज़ेरे गौर नहीं है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज वाली बात सही है या परसों वाली?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सवाल से यह सप्लीमेंटरी अराईज़ नहीं होता लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो रकम सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछले साल किसानों को व्हीट के

सिलसिले में बोनस देने के लिए थी उस बात पर विचार हो रहा है कि वह बोनस उनको कै 1 के रूप में दिया जाए या सबसिडार्डिजड फर्टीलाईज़र के तौर पर दिया जाए।

चौधरी धजा राम: क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि जो अलहदा-अलहदा को फर्टीलाईज़र एलोकेट किया जाता है उस का क्या कर्इटिरिया है। जहां पर गेहूं या पैडी ज्यादा पैदा होती है उन को ज्यादा दिया जाता है या सब जिलों को बराबर ही दिया जाता है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, खाद की एलोके 1न तो इलाके की खपत को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो ज्यादा गेहूं और पैडी ग्रोइंग इलाके हैं उनको ज्यादा दी जाती है।

चौधरी ि 1व राम वर्मा: क्या गवर्नमेंट के नोटिस में कार्इ इस किस्म की ि 1कायतें आई हैं जिस दिन खाद का भाव बढ़ा उस से एक दिन पहले या एक दिन बाद फर्जी तौर पर खाद बेची हुई दिखा दी गई? अगर यह बात सरकार के नोटिस में है तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी भजन लाल: क्या सप्लामेंट्री सवाल अराईज़ नहीं होता क्योंकि यह कोओपरेटिव डिपार्टमेंट का सवाल है, लेकिन सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं आई कि जिस दिन भाव बढ़े हो उस दिन से एक दिन पहले कोई फर्जी सेल दिखाई हो। जिस दिन भाव बढ़े थे उस दिन माकेटिंग फ़ैड्रे 1न के पास 40

हजार टन खाद का स्टॉक था और जिस दिन भाव कम था उस दिन में सिर्फ 1 हजार टन की सेल हुई, तो यह कोई एबनोरमल बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ऐसा हुआ हो तो आप मेरे नोटिस में लाएं उस की इंकवायरी करवा ली जाएगी।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, मैं इस में कुछ ऐडिशन करना चाहूंगा। मुझे कुछ लोगो ने जबानी ऐसी बातें कही हैं कि खाद का जिस तारीख को भाव बढ़ा उस तारीख को इधर उधर हुआ है। तो मैंने स्पीकर साहब उस के लिए इंकवायरी का आर्डर कर दिया है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: यह बात वैसे तो पहले भी सरकार के नोटिस में है, मगर मैं वजीर साहब से इस के बारे में पूछना चाहता हूं कि कामन पूल का जो फर्टीलाइजर आता है तो कट्टों में से फट जाने की वजह से ट्रंजिट में वजन कम हो जाता है और सोसाइटियों को कम वजन वाले कट्टे मिलते हैं लेकिन उनको आगे जमींदारो को 50 किलो वजन में पूरा देना पडता है तो फिर जो वजन भार्टेज होती है वह सोसाइटियों के जिम्मे पड जाती है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है?

चौधरी भजन लाल: यह बात ठीक है कि कई जगहो से रिक्वायर्मेंटें हमें मिली हैं कि जो हमें सेंट्रल पूल से खाद आता है उस में बोरियों का वजन कम हो जाता है। तो हमने यह फैसला

किया है कि किसान को जब हम खाद दें तो पूरा दें। तो इस वजह से इस मार्किटिंग फ़ैड्रे इन को दो करोड़ का घाटा रहा है खाद का पूरा वजन करके देने में तीन चार साल में।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: स्पीकर साहब मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब पूरा नहीं आया।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं उसमें एडी इन करता हूँ, बावजूद इस के कि हम किसान को खाद पूरा तौल कर देते हैं कुछ रिआयतें हमारे पार आ जाती हैं और फिर कुछ व्हिसप्रिंग कैम्पेन भी चलता है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी होती है। मैं हाउस को इस बात का विवादास दिलाना चाहता हूँ कि हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के नीचे एक कमेटी बना देते हैं जिस में हमारे भी मैम्बर हों और उनके भी हों और जो वह तरीका रिक्मेंड करेंगे हम उस को ही लागू कर देंगे।

राव अभय सिंह: मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया था कि महेन्द्रगढ़ जिला को एक लाख 73 हजार कट्टे दिये हैं जबकि और जिलों को पांच लाख कट्टों से भी ज्यादा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा महेन्द्रगढ़ का जिला जो पहले ही हर बात में बैकवर्ड है वहां पर भी दूसरे जिलों के बराबर खाद का कोटा क्यों नहीं दिया जाता?

चौधरी भजन लाल: हमने महेन्द्रगढ जिले को एक लाख 73 हजार 330 कट्टे दिए हैं जबकि वहां पर डिमांड इतनी नहीं थी और स्पीकर साहब वहां से लोगों की रिक्वायर्मेंट यह आई कि खाद हमें जबरदस्ती क्यों दी जाती है, जब लोगों को वहां जरूरत ही नहीं उतनी ज्यादा खाद की तो फिर राव साहब को खाद की कमी की रिक्वायर्मेंट नहीं होनी चाहिए।

चौधरी फूल चंद (मुलाना): क्या मंत्री जी के जवाब के मुताबिक खाद की सप्लाई लोगों की मांग से कम है। क्या सरकार कोई ऐसे सटैप्स उठा रही है जिस से कि वह मांग पूरी हो सके और यह भी बताएं कि हमारा सूबा कब ता फर्टीलाइजर में सैल्फ सफ़ी टैंक हो जाएगा?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमारी हमें मांग पूरी की जा रही है कि किसान को जरूरत के मुताबिक खाद दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार से कई बार कहा है हमारे मुख्य मंत्री साहब ने भी कई बार चिट्ठियां लिखी, जबानी बात की लेकिन भारत सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, बाहर से जो खाद आता है वह जितनी मिकदार में आना चाहिए, उतनी मिकदार में नहीं आता। लेकिन जितना आता है उस में से सब स्टेट्स के मुकाबले में भारत सरकार हमारा खास तौर से ध्यान रखती है और हमें ज्यादा से ज्यादा भोयर देती है, लेकिन जो कम आने की वजह से हमें थोड़ा बहुत कम मिलता है उसके लिए हम को रिक्वायर्मेंट करेंगे कि हमें और ज्यादा मिले।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं आप के जरिए सदन को इन्फरमैशन देता हूँ कि जो मैंने पहले ए योरेंस दी थी मैंने वह कमेटी बना दी है उस में चौधरी भजन लाल जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, सरदार मोहिन्द्र सिंह चट्ठा, चौधरी दल सिंह, राव निहाल सिंह, चौधरी शिव राम वर्मा, राव दिलीप सिंह, श्री भयाम लाल, श्री औम प्रकाश गर्ग और भाह हकूमत राय मैम्बर होंगे।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि व्हीट बोन देने का फैसला करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह कब तक किसानों को मिल जाएगा?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हम इस का बहुत ही जल्दी फैसला करने वाले हैं।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बताएंगे कि तरावडी मार्केटिंग सोसाईटी से जो हजारों खाद की बोरियां इधर उधर हो गई थी और इसी बिना पर जिस के एडमिनिस्ट्रेटर को भी ट्रांसफर किया गया था, उस के बारे में गवर्नमेंट ने और क्या एक निश्चय लिया है?

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, इस पर भी कमेटी गौर कर लेगी, उस में आप भी शामिल हैं।

श्री औम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब इन्होंने खाद की नई किस्म बताई हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन में से जो न

सी खाद किसान चाहे वह ले सकता है या सारी किस्म की खादें उस को दी जाती हैं?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, ऐसा है कि जो पैडी ऐरिया है खास तौर पर जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर तीन किस्म का खाद देते हैं मिलाकर और ऐसा करने से हमारी ईल्ड बढी है। दो तीन सालो से देखा गया है कि हमारी ईल्ड में कमी आई है और इस बारे एग्रीकल्चर युनिवर्सटी से रिसर्च कराई है और उनसे जानकारी हासिल की है कि कमी क्यों हुई है। उन्होंने कहा है कि किसान को सोइंग से पहले डी० ए० पी० उालना चाहिए, इससे पैदावार में इजाफा होगा। हम ने ऐसा पिछले साल से भुरु किया है और इसे सोइंग के टाईम पर देते हैं ताकि किसान बोने से पहले डी० ए० पी० डालें। ऐसा करने से पिछले साल भी ईल्ड में इजाफा हुआ और इस साल भी ऐसा करने जा रहे है।

Fertilizer Plants

***755. Sh. Dhaj Ram:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether any fertilizer plants were installed in the State during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74;and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to install any new Fertilizer Plant during the year 1974-75 in the State?

Industries Minister (Shri Harpal Singh):

(a) No.

(b) Yes.

Water Supply Scheme of Mangali

***780.Shri Amar Singh:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state whether it is a fact that the Water Supply Scheme of Mangali is not working properly, if so, the steps taken by the Government so far in the respect?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी): जी नहीं। पुरानी योजना के अनुसार जल वितरण ठीक प्रकार से काम कर रही है। एक आगमैंटे न स्कीम तैयार की गई है और इस में वृद्धि करने के लिए सफाई बोर्ड से प्र मासकिय अनुमोदन प्राप्त कर दिया गया है।

चौधरी दल सिंह: क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि गोसायी खेडा की वॉटर सप्लाई स्कीम प्रापली काम नहीं कर रही है और अगर ऐसा है तो क्या उसे ठीक करना चाहते हैं?

श्रीमती भारदा रानी: यह तो मंगाली के बारे में सवाल पूछा गया है।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहिबा बतायेंगी जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि योजना सही काम कर रही है तो क्या यह

हकीकत है कि सिर्फ हस्पताल को ही पानी मिल रहा है। और गांव को पानी नहीं मिल रहा है?

श्रीमती भारदा रानी: हमाने नोटिस में तो यह है कि सारे गांव को पानी मिल रहा है। 18 स्टैंडिंग पोस्ट्स हैं और सब काम कर रही है।

Government School for Girls

***748.Ch. Shiv Ram Verma.-**Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make separat arrangements for imparting education to girls;

(b) if so, the steps taken during the year 1973-74 in this respect together with the number of Primary, Middle and High/Higher Secondary Schools, searately, which are likelyto be converted into Girl Schools during the year 1974-75; and

(c) the total number of Government Primary, Middle and High/Higher Secondary Schools for Girls, separately, in the State at present?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) नहीं।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

(ग)

(1) प्राईमरी	136
(2) मिडल	77
(1) हाई	99
(1) हायर सैकेंडरी	20

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदया बतायेंगी वह लेडी मिनिस्टर होते हुए भी यह महसूस नहीं करती हैं कि लडकियों के लिए सैपरेट स्कूल होने चाहिए और क्या वजह है कि लडकों और लडकियों के लिए सैपरेट स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं जबकि लोगों की तरफ से इस बात की मांग की जा रही है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसकी दो तीन वजह है। एक तो लडके और लडकियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने से स्टाफ वगैरा पर खर्चा ज्यादा होगा। दूसरे हमारे यहां किसी भी स्कूल में भाहरों और कस्बों को छोड कर इतनी ज्यादा लडकियां भी नहीं है कि उनके लिए अलग से स्कूल चला सके। वैसे जो एजुके टन स्कूल हैं उन में लेडी स्टाफ रखा जाता है और लेडी टीचर्ज भी वहां पर पढाती हैं।

चौधरी िव राम वर्मा: क्या यह सही है कि लडकियां स्कूलों में इसलिए कम जाती हैं क्योंकि लडके लडकियों के लिए इकट्ठे स्कूल हैं और सैपरेट नहीं है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वहां स्कूलों में लेडी टीचर्स भी पढाती हैं और लड़कियों को पढाई की पूरी सुविधा दी जाती है।

चौधरी मनफूल सिंह: वजीर साहिबा ने फरमाया है कि लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने से खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर सैपरेट स्कूल खोल दिये जाएं तो कितना खर्चा बढ़ेगा और कितना खर्चा आएगा?

शिक्षा मंत्री (श्री माड सिंह मलिक): 1971.72 में जब सरकार ने नीति बनाई थी स्कूल अपग्रेड करने की तो सरकार ने फैसला लिया था कि आधे स्कूल लड़को के और आधे स्कूल लड़कियों के अपग्रेड किये जाएंगे लेकिन गांव की तरफ से डिमांड लड़कियों के स्कूलों के बारे में नहीं आई या बहुत कम आई और लड़को के स्कूलों के बारे में ही आई कि बनाये जाएं। लड़कियों के स्कूलों के बारे में जितनी डिमांड आई वह सब अपग्रेड कर दिए गए।

श्री धजा राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अगर कोई गांव जिस की आबादी 8/10 हजार की है और उस गांव के लोग लड़कियों का स्कूल खोलने के लिए सारी फैसेल्टीज देने को तैयार हो तो क्या वहां लड़कियों का स्कूल चालू करेंगे?

श्री माडू राम मलिक: इस वक्त तो नहीं लेकिन जब भी नए स्कूल खोलने की स्कीम बनेगी और लोगों की डिमांड आएगी और अगर लड़कियों की तादाद पूरी होगी और सारा काइटेरिया लोग पूरा करते होंगे तो बनाने के लिए तैयार है।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या इस साल कोई स्कूल अपग्रेड करने की स्कीम है?

श्री माडू सिंह मलिक: इस साल कोई स्कीम नहीं है।

राव बंसी सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि प्राइमरी से मिडल स्कूल बनाने के लिए लड़कियों की तादाद और इमारत का क्या काइटेरिया है?

श्री माडू सिंह मलिक: प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए कम से कम 40 लड़कियां जरूर होनी चाहिए।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि लोगो की तरफ से लड़कियों के स्कूल बनाने की कोई डिमांड नहीं आई तो अगर अब डिमांड आये तो अपग्रेड करेंगे?

श्री माडू सिंह मलिक: जिस वक्त मौका आएगा और ऐसी कोई योजना बनेगी तो उस वक्त देख लेंगे।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: मेरे साल्हावास हलका में मातनहेल स्कूल में लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है और लोगों

की तरफ से मांग भी है तो क्या वहां पर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का इरादा है?

श्री माडू सिंह मलिक: मैंने अर्ज किया है कि नये स्कूल खोलने की अभी कोई स्कीम नहीं है।

चौधरी जेगिन्दर सिंह भयोरण: क्या वजीर साहब के नोटिस में है कि मेरे हलका में लोहारी में मिडल स्कूल है और लोग उसे अपग्रेड करने के लिए कहते आ रहे हैं, उस बारे में क्या किया जा रहा है?

श्री माडू सिंह मलिक: मेरे इलम में तो यह नहीं आया है अगर आयेगा तो जब मौका आयेगा तो देख लिया जाएगा।

श्री के० एन० गुलाटी: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जहां जिन स्कूलों में प्योरली लड़के ही पढ़ते हैं उन में जहां हैड मिस्ट्रीसिज़ लगी हुई हैं वहां पर जेंट्स को हैड मास्टर लगाया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक: इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हैड मिस्ट्रीस भी लग सकती है और हैड मास्टर भी लग सकता है।

चौधरी िव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने का कारण यह है कि अब लड़कियां ज्यादा पढ़ गई हैं या लोग पढ़ाना नहीं चाहते या कोई और कारण है?

श्री माडू सिंह मलिक: ऐसी कांई बात नही है हम स्कूल खोलना भी चाहते थे लेकिन लोगों ने मांग ही नही की और अगर वे मांग करते तो खोलने की जितने खोल सकते थे कोर्िया करतें ।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि खांडा खेडी में लडकियों का अलग मिडल स्कूल है लडकियों की तादाद भी ठीक है और बिल्डिंग भी ठीक है और लोग भी उसे अपग्रेड करने की मांग कर रह है तो क्या उसे अपग्रेड करेगे?

श्री माडू सिंह मलिक: इस साल तो मांग आये या न आये अपग्रेड नही करने हैं ।

चौधरी चांद राम: जब हर स्टेट में लाजमी तालीम कानून लागू है तो सरकार इस बारे में इंतजाम कर रही है कि हर स्कूल गोंइग ऐज का लडका और लडकी स्कूल जायें?

श्री माडू सिंह मलिक: इस के लिए दो तरीके हैं । एक तो कानून को लागू करें और लोगों को जेल में भेजें और दूसरा परसुए ान का है । तो हम परसुए ान ही करते हैं और सारी सहूलियतें भी देते हैं, फीस भी आधी कर रखी है और दूसरी सारी सहूलियतें भी हैं ।

चौधरी राम प्रसाद: हमे लडके लडकियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने जा रहे है । लेकिन क्या यह ठीक है कि आजकल लडके और लडकियां एक साथ पढना चाहते हैं?

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जहां लडके लडकियां इकट्ठे पढते है और वहां तादाद किसी स्कूल में लडकियां की ज्यादा न हो तो क्या ऐसा कोई फार्मुला बनायेंगे कि वहां पचास फिसदी से ज्यादा लेडी टीचर्ज न हों क्योंकि लेडी टीचर्ज कंट्रोल नहीं कर सकती हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि स्कूल गोइंग ऐज के लडके लडकियों की कितनी परसेंटेज है जो स्कूल जा रही है?

श्री माडू सिंह मलिक: इस के लिए नोटिस चाहिए।

लाला रुलिया राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि जितने भी स्कूलो में लेडी टीचर्ज लगी हुई है उन से लडके कंट्रोल नहीं होते हैं इसलिए वहां पर जैंट्स टीचर लगाये जाएंगे?

श्री माडू सिंह मलिक: ऐसी बात नहीं है कि लडको को कन्ट्रोल नहीं कर सकती, आनरेबल मैम्बर को यह गलतफहमी है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनिशियल स्टेज पर स्कूल गोइंग बच्चों की तादाद में लडके और लडकियों की परसेंटेज क्या है?

श्री माडू सिंह मलिक: अगर हम 1961 से 1971 तक का मुकाबला करे तो लडकियों की स्कूल जाने की परसेंटेज 50 परसेंट बढी है और इसके मुकाबले में लडको की परसेंटेज कम हुई है।

मलिक संतराम दास बतरा: कल जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है, इसके बारे में क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि लडकियों का रिजल्ट सैटिसफैक्टरी है या लडको का।

श्री माडू सिंह मलिक: यह मिला जुला है।

श्री औम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि स्कूलों में लडकियों की तादाद बढ गई है और लडको की कम हो गई है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि लडकियों की पैदाइश ज्यादा तो नहीं हो रही है? (हंसी)

श्री माडू सिंह मलिक: लडकियों को लोग पढाने लग गए हैं, पहले नहीं पढाते थे।

Mr. Speaker: There have been sufficient number of supplementaries on this question. Next question please.

**Total number of class I, II, III and IV Government
Employees in a State**

***802. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state-

(a) the total number of class I, II, III and IV Government Employees in the State as on 31-3-1974; and

(b) the total number of Class I, II, III and IV Government Employees out of those referred to in part(a) above who belong to Scheduled Castes and Backward Classes, separately?

Mr. Speaker: Extension has been asked for answering this question which has been granted. The communication received by me in this connection is as under:

Shyam Chand, D.O. No. 4660-SW-1-74/14063

मंत्री,

Social Welfare & Taxation विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़।

Dated 9th July, 1974

Subject:- Starred Assembly Question No. 802, asked by Ch. Dal Singh, M.L.A. regarding total number of Government Employees in the State

My Dear Shri Sarup Singh,

I write to inform you that Starred Vidhan Sabha Question No. 802 to be asked by Chaudhry Dal Singh M. L. A. stands in the name of Social Welfare and Taxation Minister. The question has been fixed for answer on 11-7-1974. The requisite information was called from all departments in the State, but many Departments have not sent the replies as yet. I shall therefore, feel grateful if this question is fixed for answer on any day during the next assembly session.

Yours Sincerely,

Sd/-Shyam Chand

(Shyam Chand)

Shri. Sarup Singh

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha

Chandigarh

चौधरी चांद राम: इस में एक्सटेंशन मांगने की कोई बात नहीं है। हर डिपार्टमेंट के पास एक रोस्टर होता है जिस में यह इनफॉर्मेशन मौजूद होती है और यह स्टेट हैड-क्वार्टर अप अवेलेबल हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: सवाल में सारे इम्प्लाइज यानी क्लास 1, 2, 3 तथा 4 का नम्बर मांगा है और उस में भोड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के एम्प्लाइजका भी नंबर मांगा है। इस इन्फॉर्मेशन को कुलैक्ट करने में सर्वेनली कुछ समय चाहिए।

चौधरी चांद राम: हर डिपार्टमेंट ने रोस्टर रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिस में यह सारी इनफॉर्मेशन अवेलेबल है और उस में से कुलैक्ट करके दी जा सकती है।

Mr. Speaker: Extension had been asked for in respect of this question which has been granted. Next question please.

Ch.Chand Ram: Till when?

Mr. Speaker: Next question now.

Per Capita Expenditure on Medical Aid

***807. Ch. Mehar Chand:** Will the Minister for industries be pleased to state the maximum point touched upto May, 1968 and May, 1974, separately, in respect of medical aid in terms of per capita annual expenditure?

गृह तथा स्वास्थ्य: मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):
चिकित्सा सहायता संबंधित अधिकतम प्रति व्यक्ति खर्चा मई, 1968 तक 4 रुपये 77 पैसे था और मई, 1974 तक 12 रुपये 23 पैसे था।

चौधरी मेहर चंद: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि इन्होंने जो 12 रुपये 23 पैसे की फिगर दी है, क्या यह मई, 1974 की है या इससे पहले की है? अगर इससे पहले की है तो सबसेक्वेंट ईयर की क्या फिगर है?

श्रीमती भारदा रानी: फिर से कहना मैंने सुना नहीं।

चौधरी मेहर चंद: मैं दोबरा अर्ज कर दूँ। मेरा क्वै चन मंत्री महोदया यह है कि

चौधरी बंसी लाल: चौधरी साहब, चेयर को ऐड्रेस करें, लेडी मैम्बर को क्यों कर रहे हो? (हंसी)

चौधरी मेहर चंद: मैं यह जानना चाहता हूँ कि 12 रु 23 पैसे की जो फिगर मंत्री महोदया ने बताई है क्या यह मई,

1974 के पहले की है? मैंने पूछा था कि “the maximum point touched upto May,1968 and May,1974, separately in respect of medical aid in terms of per capita annual expenditure?” यह पहले ईयर की भी हो सकती है। पर—कैपिटा एक्सपेंडिचर की फिगर 12 रु 23 पैसे तक पहुंच चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह 12 रु 23 पैसे किस साल की फिगर है? अगर यह मई, 1974 से पहले की है तो what is the position in subsequent years?

श्री मती भारदा रानी: यह 1973-74 की पोजी न है। सब्सीक्वेंट ईयर तो चल रहा है, इस में पोजी न थोड़ी कम हो गई है और उसकी फिगर 11.04 रु है।

चौधरी िव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बातयेंगी, जैसा कि उन्होंने कहा है, मई,1968 में 4.77 रु पर—कैपिटा एक्सपेंडीचर है। क्या यह दवाईयों का खर्चा है?

श्री मती भारदा रानी: यह पूरी मैडीकल एड का है।

चौधरी िव राम वर्मा: जैसा कि मंत्री महोदया ने बताया की मई, 1974 में 12.23 रु पर—कैपिटा एक्सपेंडिचर था। इस वक्त के भावों को देखते हुए क्या ये दवाईयां इतने रुपये में आ जाती है या नहीं?

श्री मती भारदा रानी: मैंने तो पूरी मैडिकल—एड का बताया है जिसमें हास्पिटल डाक्टर वगैरा का खर्च सब कुछ आ जाता है। जो स्वास्थ्य विभाग का बजट होता है उस में जो पैसा

होता है वह मैडिकल एड पर खर्च होता है और उसमें से जो पैसा दवाईयों के लिए एलोकैट किया जाता है वह दवाईयों पर खर्च होता है।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इन्होंने मई, 1974 की टोटल पर-कैपिटा एक्सपेंडिचर बताई है 12.23 रु और मई 1968 की 4.77 रु बताई है। आपको मालूम है कि इन आठ सालों में कितनी महंगाई बढ़ी है। तो इस के मुताबिक 1968 के 4.77 रु और 1974 के 12.23 रु एक जैसे नहीं बैठते?

चौधरी बंसी लाल: यह हिसाब तो आप ही लगा लेना (हंसी)

Loharu Irrigation Scheme

9820. Malik Sat Ram Dass Batra: Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total area irrigated by the Loharu Lift Irrigation Scheme in the year 1973;

(b) whether the entire project has been completed; if so, the total amount spent on this project upto 31st March, 1974; and

(c) the estimated increase in the annual production of food grain by the use of the water of this project?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) 25,621 acres.

(b) it is 95% complete.

Expenditure upto 31-3-74 is Rs. 12.41 crores including cost of construction, machinery, that will be transferred to other projects and credit received.

(c) The estimate value of additional foodgrain produced in different years is under:-

1971-Rs. 43 lakhs

1972- Rs. 134 lakhs

1973-Rs. 256 lakhs

मलिक संतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस स्कीम से कितने गावों को पानी दिया है या कितने गांव इस काबिल हैं जहां पानी लग सकता है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: यह 94 विलेजिज़ को प्रोजैक्ट है। 5 परसेंट गांव रहते हैं। बाकी सब को पानी लग चुका है।

मलिक संतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जमींदार को रबी के सीज़न में कितनी बार पानी देते हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: यह पैरीनियल नहर नहीं है, फ्लड-वाटर देते हैं और इस दफा हमने सर्दी के मौसम में भी

पानी देने की कोशिश की। जितनी देर तक यह देते यह पैरीनियल नहीं होती, हम फ्लड वाटर ही देंगे।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह पानी बरसात के दिनों में ही देते हैं या बरसात न होने पर भी देते हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: हमने पांच सालों में 3 हजार क्यूसिक पानी आगमैंट किया है, बढ़ाया है। एक बात मैं मैम्बर साहबा को बता दूँ कि किसी एरिये का पानी काट कर नहीं देते।

चौधरी चांद राम: मैंने यह नहीं पूछा था मैंने पूछा था कि जैसा कि इन्होंने कहा कि फ्लड वाटर देते हैं और फ्लड वाटर रेनी-सीज़न में आता है। क्या आप पानी तब देते हैं जब रेनी सीज़न होता है या रेनी सीज़न के न होने पर भी देते हैं?

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि फ्लड रेनी-सीज़न में आता है लेकिन जिस एरिया को पानी देने के लिए यह योजना तैयार की गई है वह एरिया ऐसा है जहां रेनी-सीज़न में भी कई बार तीन-तीन चार-चार साल तक एक बूंद नहीं पड़ती। मैं उस इलाके का भुक्तभोगी हूँ, वहां का रहने वाला हूँ। अम्बाला तथा जगाधरी के इलाकों में बारिश से दरियाओ में काफी पानी आता है लेकिन लोहारु के इलाक में एक बूंद पानी

की नहीं बरसती। कम से कम हमने उस बाढ़ के पानी को कई जो इलाकों को तबाह किया करता था, चैनललाईज करके उस इलाकों को दिया जहां रेनी-सीजन में भी एक बूंद तक नहीं पड़ती थी।

Multi-Purpose Beas Project

***832. Shri Om Parkash Garg:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that State of Haryana is a partner State in the Multipurpose Beas Project;

(b) if so, the name of those units of which this project is comprised of;

(c) the manner in which the State of Haryana will be benefited by each of the units; and

(d) the time by which these units are likely to be completed?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Yes.

(b)

(i) Unit No. I (Beas Sutlej Link) and

(i) Unit No. II (Beas Dam)

(c) The benefits from the Project Unit-I and II are availability of water for irrigation, and power.

(d)

(i) Unit No. I (Beas Sutlej Link) : By June, 1976

(i) Unit No. II (Beas Dam) L By June, 1974.

Low and Middle Income Group Housing Scheme

***841. Shrimati Lajja Rani:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total number of houses constructed by the Haryana Housing Board under the Low and Middle Income Group Housing Schemes, separately, upto 31st March, 1974;

(b) the terms and conditions on which these houses were sold to the people; and

(c) the target which is likely to be achieved during the year 1974-75 alongwith the places of their construction?

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):

(ए) से (सी) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ए) भून्य

(बी) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सी) वर्ष 1974.75 में जो लक्ष्य पूरे करने हैं वह स्थान तथा स्कीम सहित निम्न प्रकार है:

स्थान का नाम	एम0 जी0	आई0	एल0 जी0	आई0	कुल संख्या
फारीदाबाद	164		252		416
पानीपत	51		19		70
सोनीपत	78		16		94
यमुनानगर	25		6		31
अम्बाला फेज़ 1	28		15		43
करनाल फेज़ 1 तथा 2	132		64		196
पंचकुला	51		84		135
पानीपत फेज़ 2	27		13		40
	556		469		1,025

इस साल लो इन्कम ग्रुप स्कीम के तहत 556 मकान, मिडल इन्कम ग्रुप स्कीम के तहत 469 मकान और टोटल 1025 दोनों स्कीम्ज़ के तहत बनाए जाएंगे।

Ch. Mehar Chand: May I know from the Hon. Minister the steps taken to Provide cheap type of roofed accomodation to the labourers who are working in various Mandis of the State and are without houses?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के लिए पूरी चेश्टा कर रह हैं कि जो बहुत गरीब आदमी हैं, झुग्गी झोपडी में रहते हैं या बिना मकान के आदमी हैं उनके लिए सस्ते मकान बनवाएं। कई जगह से स्कीम्ज़ मंगवाई है और दो तरह के ऐस्टिमेट्स हमने तैयार करवाए हैं। जो हमारा पीछडा हुआ वर्ग है उसके लिए ई० डबल्यू० एस० टाईप मकान बना दिए हैं। दस हजार रुपये से ऊपर उसकी लागत आती है। बहुत गरीब लोग जो हैं, जो इतनी कीमत भी बर्दा त नहीं कर सकते और उसकी किस्त भी नहीं दे सकते, उनके लिए हमने दो ऐस्टिमेट्स और तैयार करवाए हैं। एक तकरीबन पांच हजार रुपये की कीमत का मकान है और दूसरा साढे तीन हजार रुपये की कीमत का मकान है। इनको बनवाने की योजना बोर्ड के और सरकार के विचाराधीन है। जब यह स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसे गरीब लोगों के लिए भी मकान तैयार करवाएं जाएंगे।

श्री अमर सिंह: क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेगें कि वर्ष 1974-75 में लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम और मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत जिन 1025 मकानों के बनाए जाने का जिक अभी-अभी महोदय ने किया उनमें भिवानी और हिसार का बिल्कुल ही नाम न होने का क्या कारण है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, भिवानी और हिसार के अंदर इस वर्ष जमीन अक्वायर कर रहें हैं। भिवानी में तो जमीन भी देख ली गई है और वहां रजिस्ट्रेशन का काम भी

भारु हो चुका है। हिसार के बारे में अभी नहीं कह सकता। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज़ पर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कॉलोनी बनाने की तज़बीज़ है।

राव अभय सिंह: रिवाडी एक बहुत बड़ा भाहर है। लेबर भी वहां बसती है। क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि हाउसिंग बोर्ड ने वहां भी कोई स्कीम तैयार की है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अभी तक तो नहीं की है लेकिन अब स्कीम तैयार कर रहे हैं।

श्री मती लज्जा रानी: क्या दादरी में भी यह स्कीम बनेगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: दादरी में भी बनवाएंगे लेकिन अभी तक दादरी के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कीमत मुकर्रर की जाती है इसका क्या काइटेरिया है?

श्री बनारसी दास गुप्त: मकान की कीमत में एक तो मकान बनाने पर जो ऐक्चुअल कीमत आती है वह भामिल होती है और उसके साथ डिवैल्पमेंट चार्जिज़ भामिल होते हैं जैसे सीवरेज स्कीम है, गली पक्की करनी है, वाटर सप्लाई स्कीम है, स्ट्रीट

लाईट है। ये तमाम एमेनिटीज़ उस कॉलोनी के अंदर प्रोवाइड की जाती है और इनका खर्च भी मकान की कीमत में डाला जाता है।

श्री बिहारी लाल वाल्मीकि: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर नगरपालिकाओं और नोटिफाइड कमेटीज़ के अधीन सफाई का काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हैं, जो गंदगी का पेना करतें हैं, सुबह उठ कर गंदगी में जाते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात में भी जो गंदी बस्तियों में टूटी झोपड़ियों में रहते हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके लिए भी कोई सस्ते मकान बनाने की स्कीम है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, सफाई मजदूरों के लिए भी सस्ती टाईप के मकान बनाने के लिए हम विचार कर रहे हैं।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि सफाई मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना पर भी सरकार विचार कर रही है। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन गरीब आदमियों के पास मकान बनाने के लिए जमीन भी नहीं है उनको प्लॉट भी प्रोवाइड करने का सरकार का कोई विचार है?

श्री बनारसी दास गुप्त: हमारे प्रदेश में ऐसे जो होमलैस पीपल हैं उनको होम साइट देने का भी सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है।

चौधरी चिंतामणि राम वर्मा: स्पीकर साहब, केवल भाहरों में रहने वाले कम आय वालों के लिए और गरीबों के लिए ही यहां बातें बताई जा रही हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गावों में जो कम आमदनी वाले लोग रहते हैं, हरिजन लोग रहते हैं, बैकवर्ड क्लासिज के लोग रहते हैं उनको भी आबादी के लिहाज से इसी तरह की प्रैफरेंस दी जाएगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी एक प्रश्न के उत्तर में, भायद वर्मा जी ने ही पूरक प्रश्न किया था, बतलाया था कि इस वक्त ज्यादा गंभीर समस्या मकानों की भाहरों में है। यह ठीक है कि देहात के अंदर भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं हैं, जमीन नहीं है। उधर भी हम ध्यान दे रहे हैं और ऐसी स्कीमें बना रहे हैं लेकिन प्राथमिकता भाहरों को इसलिए दे रहे हैं कि वहां आवास की समस्या गंभीर थी।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, बैकवर्ड क्लासिज के लोगो को हरिजन वेलफेयर स्कीम के तहत मकान बनाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वह साढ़े बारह सौ रुपए दी जाती है और उसमें आधा पैसा बनिफिट एरिज को खुद लगाना होता है। उनके लिए तो ढाई हजार तीन हजार रुपये का ऐस्टेट बना दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड क्लासिज वेलफेयर स्कीम के तहत जो रकम दी जाती है उसको भी इतना ही बढ़ाने की कोशिश की जाएगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, अभी हाउसिंग बोर्ड तीन प्रकार के टाईप्स के मकान बना रहा है। एक इकनोमिकली वीकर सैव इन के लिए, जिसकी कीमत दस हजार रुपये से ऊपर है, एक लो इन्कम ग्रुप के लिए, एक मिडल इन्कम ग्रुप के लिए और अब हम विचार इस बात का कर रहे हैं कि दस हजार रुपया वीकर सैव इन के लिए बहुत ज्यादा है। कम कीमत के सस्ते मकान की हम तजवीज़ कर रहे हैं, उसके लिए जांच करा रहे हैं और ऐस्टिमेंट तैयार करा रहे हैं।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि सफाई कर्मचारियों के लिए और अन्य जो लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए योजना विचाराधीन है। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि वह योजना कब भुरु होगी। कब तक पुरी हो जाएगी और उसको इम्प्लीमेंट होने में कितना समय लगेगा?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न पर काफी सप्लीमेंटरी हो चुकी है, अब हम नैक्सट क्वेश्चन टेक-अप कर लेते हैं। अभी तक आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं जबकि टाईम खत्म होने वाला है। चौधरी पोकर राम गोदारा।

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Consumption of Chemical Fertilizer

***852 Sh. Behari Lal Balmiki:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state the total consumption of chemical fertilizer in the State during the year 1973-74?

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): 5,80,696 टन
(साधारण रासायनिक खाद के रूप में)

500 Beds Hospital

***859. Sh. K. N. Gulati:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that land has been purchased for the construction of 500 beds Hospital at Faridabad; and

(b) if so, time by which the construction of the Hospital is likely to be started?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):

(ए) नहीं।

(बी) लागू नहीं होता।

श्री के० एन० गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी जो फरीदाबाद में सैक्टर 8 में 500 बैड्स के लिए जमीन ली है?

श्रीमती भारदा रानी: जी अभी नहीं ली।

श्री के० एन० गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी जो फरीदाबाद के 90 प्रतिशत सीरियस मरीज होते हैं वे दिल्ली चले जाते हैं क्या सरकार वहां पर कोई बड़ा हस्पताल खोलेगी ताकि हरियाणा के लोगों का हरियाणा में ही इलाज हो जाए?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, इस समय फरीदाबाद के 200 बैड्स का एक अच्छा हस्पताल है। इसके अतिरिक्त क्योंकि वहां पर मजदूर एरिया है एक बहुत अच्छा हस्पताल ई० एस० आई० का भी है। वह 50 बैड्स का है। ई० एस० आई० की वहां पर कई डिस्पेंसियां हैं लेकिन फिर भी वहां सरकार का ऐसा विचार था कि 500 बैड्स का एक हस्पताल खोला जाए इसके लिए एकाध जगह जमीन भी देखने की कोशिश की गई लेकिन इस समय हमारे फायनेंसियल स्ट्रिजेंसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि पांच साल प्लान में यह संभव नहीं हो सकेगा।

श्री के० एन० गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि गोल्फ क्लब की जमीन जो टाउनशिप में है उसको एक्वायर करके वहां पर हस्पताल खोला जाएगा?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, जब पैसा ही नहीं है तो जमीन खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वहां

गोल्फ क्लब की जमीन का तो कोई प्र न ही पैदा नहीं होता है। वह जमीन तो टुरिज़म के कामों के लिए उचित समझी गयी है।

श्री धजा राम: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जींद का सिविल हस्पताल पिछले सालों से बन रहा है और उसकी बिल्डिंग को, मैं नहीं समझता क्यों बनाने से रोका है? क्या उसको भीघ्र से भीघ्र बनाने की कृपा करेंगे?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, जींदका जो हस्पताल है उसमें कुछ देरी हो गई है क्योंकि पी० डबल्यू० डी० महकमेंके बीच और ठेकेदार के बीच किसी बात पर झगडा हो गया और वह झगडा काफी समय तक कोर्ट में चलता रहा। इसके कारण उसका काम बंद हो गया लेकिन अब उसको जल्दी से जल्दी बनवा रहे हैं।

श्री मलिक संतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि बाद ग़ाह खान हस्पताल जो फरीदाबाद में है उसकी एक्स-रे मीन खराब है और स्टोर का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं है और वहां पर जो मैस है वह भी बिल्कुल खराब सा है, क्या वहां का आप निरीक्षण करेंगी?

श्रीमती भारदा रानी: मैं उधर की ही रहने वाली हूं। बाद ग़ाह खां हस्पताल का बहुत बार निरीक्षण किया है। एक्स-रे मीन का प्र न पिछले सै ान में भी आया था उस समय मालूम किया था, वहां मीन ठीक काम कर रही है।

चौधरी पीर चंद: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी जैसा कि उन्होंने और हस्पतालो के मुत्तालिक भी यहां बताया है, मेरे अपने हलके में हसनगढ गांव है जिसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर डिसपेंसरी खोलने की कृपा करेंगे?

श्रीमती भारदा रानी: अब य विचार कर लेंगे ।

राव अभय सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि रिवाडी के हस्पताल को बनते हुए कोई डेढ साल हो गया और अब वहां पर काम बिल्कुल बंद है, इसका क्या कारण है?

श्रीमती भारदा रानी: डेढ साल नहीं हुआ है कुछ समय हुआ है लेकिन वहां पर जितने रुपये का एस्टीमैट है उतना पूरा रुपया उपलब्ध नहीं हो रहा है फिर भी वहां पर काम चालू है । कम से कम 50 परसेंट इससाल में या अगले साल तक बना दिया जाएगा ।

श्री गौरी भांकर: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जो हस्पताल नरवाना में बन रहा है वह कब तक तैयार हो जाएगा?

श्रीमती भारदा रानी: वह जल्दी से जल्दी तैयार कर देंगे ।

श्री बिहारी लाल वाल्मीकि: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि औरंगाबाद में जो हस्पताल टूटा हुआ है,

जिसको करीब छः साल हो गये हैं और एक साल भर से तो ठेकेदार ने वह बिल्डिंग ही खराब कर दी है?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद में कोई सिविल हस्पताल नहीं है। वहां पर एक प्राईमरी हैल्थ सेंटर है। इस प्र न का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी हमें प्राईमरी हैल्थ सेंटर की बिल्डिंग का ध्यान है उसको भी देखेंगे कि उसकी रिपेयर वगैरह की जाए।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि हांसी में हस्पताल की छत गिरी हुई है, उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा?

श्रीमती भारदा रानी: उसकी रिपेयर के लिए 50-60 हजार रु का प्रबंध किया जा चुका है। यह हमारे नोटिस में है कि हांसी के हस्पताल की बिल्डिंग बहुत खराब है। जैसे ही हमें हस्पताल की बिल्डिंग के लिए कोई पैसा प्राप्त होगा, हांसी और पलवल के हस्पताल को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि नारायणगढ में जो हस्पताल बना है वह तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है, उसको कब तक चालु करने का विचार है?

श्रीमती भारदा रानी: वह तो बराबर चालू है।

Tubewells

***883 Ch. Ram Parshad:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of tubewells which were in working order together with the number of tubewells which were out of order in the Bawal Constituency during the period from 1st January, 1974 to 30th April 1974 separately?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):-

Month	No. of tubewells in existence	Tubewells in working order	No. of tubewells out of order
January, 74	19	17	2
February '74	23	20	3
March '74	27	24	3
April, 74	27	27	Nil

चौधरी राम प्रसाद: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवैल खराब पड़े हैं उन को ठीक करवा कर चालू कर देंगे? क्या वे इसी साल में चालू हो जाएंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, ये ज्यों ज्यों ट्यूबवैल लगा रहे हैं उन को चालू किया जा रहा है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उसको भी जल्दी दूर करेंगे।

चौधरी फूल चंद (मुलाना): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अम्बाला में जो ट्यूबवैल लगे हैं उन में से बहत से आउट आफ आर्डर हैं, कईयों के नंबर साल भर से दिए गए हैं लेकिन वे अब क नहीं लगे, वे कब तक लगेगें और जो खराब पडे हैं वे कब तक ठीक हो जाएगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, यह बावल के एरिये का सवाल है, तहसील अम्बाला की बात यह है कि वहां पर ट्यूबवैल काफी बोर हो चुके हैं। काफी को चालू किया जा चुका है, मेरी अपनी कांस्टीच्युएंसी में काफी ट्यूबवैल लगे हुए हैं जो अभी तक चालू नहीं हो सके। इन को जल्दी से जल्दी चालू करने की कोशिश की जा रही है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवैल लगाते हैं वह चाहे बावल के एरिया में है चाहे अम्बाला जिले में है, लोगो से एम० सी० जी० लेते हैं। क्या आप एग्रीमेंट में यह कहेंगे कि अगर पानी नहीं दिया जाएगा.....

Mr. Speaker: I do not allow supplementary to this question. It does not arise out of it.

श्री औम प्रकाश गर्ग: कुरुक्षेत्र में जो डायरेक्ट इरीगेशन के ट्यूबवैल लगे हैं कितने खराब पडे हैं और कितने चालू हैं?

Mr. Speaker: The main question is about Bawal constituency only.

Colleges in Jhajjar Tehsil

***890. Ch. Phul Singh Kataria:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of colleges functioning in Tehsil Jhajjar on 31st March, 1974;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a new college exclusively for girls in Jhajjar Tehsil; and

(c) the details of the Government Colleges and Private Colleges functioning at present in Tehsil Jhajjar?

शिक्षा एवं परिवहन मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(ए) चार

(बी) नहीं

(सी) राजकीय और अराजकीय कॉलेजों के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1. नेहरू कॉलेज झज्जर

अराजकीय कॉलेज

1. हरियाणा महाविद्यालय बेरी

2. ग्राम भारती महाविद्यालय नाहड

3. इन्द्रा कॉलेज दूबलधन

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि इस तहसील में लडकों के तो कालेज हैं लेकिन लडकियों का कोई कालेज नहीं। क्या सरकार का लडकियों का भी कोई कालेज खोलने का विचार है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: ऐसी कोई विचार नहीं कि लडकियों का अलग से कोई कालेज खोला जाए।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि वहां लडकियों का कालेज खोलने का क्यों विचार नहीं है, क्या वहां लडकियां पढना नहीं चाहती क्योंकि अभी मंत्री महोदया ने बताया है कि वहां लडकियों का कालिज खोलने का कोई विचार नहीं है। अगर लोग लडकियों का कालेज बनाना चाहें तो क्या सरकार उनकी मदद उसके बनाने में करेगी?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): लडको के कालेज के तीन फाउंडे इन स्टोन रखे गए थे। वे अभी तक नहीं बने हैं, पहले आप उन को तो बना लो।

श्री के० एन० गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि वल्लभगढ के एरिया और फरीदाबाद के एरिया में इस वक्त आबादी बढ चुकी है लेकिन वहां पर एक कालेज बी० ए०

तक का है। क्या वहां पर बी० ए० बी० टी० और एम० एड० की क्लासिज़ खोली जाएगी?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): कालेज फरीदाबाद में चालू है, एम० एड० क्लासिज़ तो युनिवर्सिटी में है, अगर युनिवर्सिटी ठीक समझेगी तो चालू कर देगी।

श्री के० एन० गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि गवर्नमेंट कालेज फरीदाबाद में आलरेडी इवनिंग क्लासिज़ चालू हैं। क्या वहां पर इवनिंग कालेज में एम० ए० क्लासिज़ की इजाजत दी जाएगी?

Mr. Speaker: The question Hour is over now.

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Hydro-Electric Projects

***872. Ch. Ram Kishan Azad:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the names of the Hydro-Electric Projects from which the State will get electric power;

(b) the quantity of the power which the State will receive from each such project; and

(c) the time by which the power is likely to be received from these projects?

Irrigation and Power Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): (a), (b) and (c).

A. Statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

Statement

Name of Hydro-Electric Project (a)	Haryana's share of power. (b)	Likely year of Commissioning. (c)
1. Beas Unit-I Stage-I	212 Mega Watt.	1976-77
2. Beas Unit-I Stage-II	105 Mega Watt.	1978-79
3. Beas Unit-II	40 Mega Watt.	1977-78
4. Siul Hydro-Electric Project	55 Mega Watt.	1977-78
5. Salal Hydro-Electric Project.	50 Mega Watt.	1979-80

However, the likely year of commissioning of each project depends upon the timely clearance by Govt. of India, availability of the materials and labour trouble.

Taccavi and Crop Loans

***875. Ch. Brij Lal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total number of Taccavi and Crop Loans given to the farmers in the years 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1970-71, 1971-72, 1972-73 and 1973-74, separately; and

(b) the main conditions on which the crop loans are given to farmers?

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Statement is laid on the table of the House.

Statement showing the Taccavi and Crop Loans given to the farmers by the
Agriculture/Revenue/Cooperation Departments.

Year	Fertilizer	Tractor	Minor Irrigation	Horticulture	Soil Conservation (Rs. in lakhs)	Integrated Dry land Agricultural Development Project	Aerial Spray	Act 1883(i) ordinary (Taccavi loan Rs. in lakhs)	Act XIX (b) other loans	Act XII of 1884(i) other loans	(Crop loan) (Rs.in lakhs)
1967-68	246.32	5.50	115.25	2.09	12.18	-	-	4.74		25.44	911.35
1968-69	246.69	-	13.00	2.63	9.11	-	0.54	3.50		23.51	1287.71
1969-70	198.18	-	3.68	1.31	-	-	3.00	7.95		28.21	1636.47
1970-	568.38	-	12.51	1.07	-	13.80	1.08	3.50		23.77	1585.03

71										
1971-72	-	-	-	1.38	-	0.68	2.50	3.76	44.23	1981.63
1972-73	-	-	-	-	-	-	4.00	3.85	59.11	2249.46
1973-74	-	-	-	-	-	-	23.46	4.02	18.42	2164.10

The total maximum credit limit of a farmer member is fixed for Rabi & Kharif Crops on the basis of area to be brought under cultivation multiplied by the scale of Finance prescribed by the Agriculture department which is Rs. 125/-per acre for cash portion. The highest limit for an individual is Rs. 3000 in Barani Areas . Rs. 4000/- in irrigated areas and Rs. 5000/- for sugar cane. Such loans are advanced by the village Coop. Credit Societies on personal surties of 2 members. The rate of interest charged from the ultimate borrower is 10.50%. The loan is repayable within a year.

Statement is laid on the table of the House.

***877. Sh. Prem Sukh Dass:** Will the Minister for Agriculture be pleased to State-

(a) the production of Oil seeds in the state in the year 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1972-73 and 1973-74 separately;

(b) the total area of land in the State where Oil Seeds were produced in the years mentioned in part (a) above, separately; and

(c) whether more area is likely to be brought under cultivation for the production of Oil Seeds during the year 1974-75, if so, the approximate area thereof.

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Statement is laid on the table of the House

Statement

(a) The production of Oil Seeds during various years is given as under:-

Year	Production ('000 tonnes)
1968-69	43.0
1969-70	89.0
1970-71	99.0
1971-72	99.0
1972-73	106.4
1973-74	60.

(b)

Year	Area ('000 hectares)
1968-69	84.0
1969-70	135.0
1970-71	142.0
1971-72	176.0
1972-73	221.7
1973-74	223.0

(c) The area under Oil Seeds is likely to increase from 2,30,000 hectares in 1973-74 to 2,40,000 hectares during 1974-75.

Consumption of Fertilizer

***879. Rao Abhai Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total consumption of chemical fertilizer in the State in the years 1968-69, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73 and 1973-74, separately;

(b) the total consumption of chemical fertilizer per hectare in the State in the years mentioned in part (a) above, separately; and

(c) whether the Government intends to procure and supply more fertilizer to the farmers at subsidized rates?

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) Statement is laid on the table of the House.

(b) Consumption per hectare is given as under.

Year	Kgs.
1968-69	64
1969-70	73
1970-71	99
1971-72	115
1972-73	127
1973-74	157

(c) No.

Statement

Consumption of fertilizers in terms of straight fertilisera
(in tonns)

Year	In terms of ammonium sulphate 20%	In terms of Superphosphate 16%	In terms of Muriate of Potash 60%	Total
1968-69	201625	34457	1980	238062
1969-70	235000	32000	3000	270000
1970-71	304860	42880	3710	351450
1971-72	352270	39056	4068	395394
1972-73	415530	50930	4360	470820
1973-74	470300	102956	7440	580696

Total	1979585	302279	24558	2306422
--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Per Capita Expenditure on Health/Medicines.

***900. Sh. Hari Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the per capita expenditure for health in the years 1967-68 and 1973-4 in the State, separately;

(b) the per capita expenditure on medicines in the years 1967-68 and 1973-74 in the State separately; and

(c) the approximately total expenditure on the health services in the years 1967-68 and 1973-74 separately?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh):

(a)

1967-68	Rs. 4.77
1973-74	Rs. 12.23

(b)

1967-68	Rs. 0.21
1973-74	Rs. 0.82

(c)

1967-68	Rs. 4,21,96,240
1973-74	Rs. 12,86,69,350

Licences for Liquor Shops

***800. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state the district-wise total number of new licences issued for Indian made foreign liquor and Beer Shops in the State during the year 1973?

Social Welfare & Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): A statement is laid on the table of the House.

Statement

Number of Licences issued during the year 1973

Name of the District	No. of licences for sale of IMFS including beer	No. of licences for sale of beer only	Total
Hisar	12	1	13
Rohtak	13	-	13
Gurgaon	29	2	31
Karnal	8	-	8
Ambala	9	-	9
Mohindergarh	8	1	9
Bhiwani	6	1	7
Sonepat	4	-	4
Jind	1	-	1
Kurukshetra	6	1	7

	96	6	102
--	----	---	-----

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी एक रिक्वैस्ट है? दो रैजोल्यूशन हैं, इन पर अगर टाईम फिक्स कर दिया जाए तो ठीक रहेगा क्योंकि इससे दोनों ही रैजोल्यूशन डिस्कस हो जाएंगे।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है कि आप इसको....

Mr. Speaker: You will get the reply.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, वह तो मुझे मिल गया है। आपका बहुत-2 भुक्तिया। मैं थोड़ी सी सबमिशन करना चाहता हूँ। यह मामला किसी पार्टी का नहीं है.....

Mr. Speaker: It is not in order. I have rejected it.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ। आपका जवाब तो मुझे मिल गया उसके लिए आपका बहुत बहुत भुक्तिया। मेरी सबमिशन यह है कि इसमें आपने जो दो तीन एतराजाज दिए हैं, उनमें एक तो यह है कि यह रीसेंट अकरेंस का नहीं है.....

Mr. Speaker: When it has been rejected there can be no discussion.

चौधरी चांद राम: हम आपसे दोबारा अपील तो कर सकते हैं?

Mr. Speaker: You can give another notice.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, आपने रिजैक्ट तो कर दिया, वह ठीक है। आप मेरी सबमिशन तो सुन लो, सुनने के बाद आप फिर रिजैक्ट कर सकते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट मामला है.....

Mr. Speaker: You can come to my chamber and discuss it with me.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी रिक्वेस्ट यह है कि हमें यह पता नहीं था कि इसके बारे में ऐडजर्नमेंट मोशन आया हुआ है। हमने भी इसके लिए जो ऐडजर्नमेंट मोशन दिया था वह इसलिए दिया था कि हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस पर कोई स्टेटमेंट दे दे तो हमारी सैटिसफैक्शन हो जाए। हमें ऐडजर्नमेंट मोशन देने का कोई भावुक नहीं था। हमें इनके ऐडजर्नमेंट मोशन का पता नहीं था इसलिए हमने भी इसी प्वायंट पर ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है। मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम उनसे सिर्फ यह चाहते हैं कि वे अगर इस बारे में कोई स्टेटमेंट दे दें तो स्पष्टीकरण हो जाएगा और हाउस में यह इन्फर्मेशन आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आपने जो ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है That I will examine.

चौधरी राम लाल वधवा: जो डिस्मिशन एक पर हो गया, वही इस पर होगा मगर हम तो आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर वे कोई स्टेटमेंट दे दें तो हमारी समस्या हल हो जाएगी।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, गुजारिए। यह है कि यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है और अगर गवर्नमेंट इस पर स्टेटमेंट दे दे

तो पब्लिक के दिलो में भाक नही रहेगा। गवर्नमेंट यह बता दें कि उसकी इस बारे में क्या पोजी उन है?

Mr. Speaker: Order please. I have already decided it. The adjournment motion for which another notice has been received today is under my examination.

Rao Bansi Singh may please move his resolution now.

गैर सरकारी संकल्प

ज़िला महेन्द्रगढ़ के सूखे तथा पिछड़े क्षेत्रों में पानी के (मीठे) पानी की नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई के लिए तुरन्त आवश्यक प्रबंध किए जाने के संबंध में।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, दोनो ही रैजोल्यूशन के लिए कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि इससे दोनो रैजोल्यूशन डिस्कस हो जाएंगे।

Mr. Speaker: It is for the House to decide. The House can discuss two resolutions or three resolutions or it may discuss one resolution. It is for the House to decide.

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, दोनो रैजोल्यूशन अपोजीशन की तरफ से हैं और अगर ये आपस में टाइम का बंटवारा कर लें तो हमें कोई एतराज नहीं।

चौधरी राम लाल वधवा: राव सिंह जी, अगर आधा आधा टाइम इन दोनो रैजोल्यूशन पर रख लें तो ठीक रहेगा।

राव बंसी सिंह: जो रैजोल्यू इन मैं ला रहा हूँ वह रैजोल्यू इन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यह चाहूंगा कि मैम्बर्ज इस पर बोले। अगर बाद में टाईम बच जाए तो दूसरा रैजोल्यू इन भी डिस्कस हो सकता है।

Mr. Speaker: Now the Hon. Member may please move his resolution.

Rao Bansi Singh (Ateli): Sir, I be to move-

That this House recommends to the State Government to make immediate necessary arrangements for the regular adequate supply of drinking water (sweet) in the drought and backward areas of District Mahendergarh.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House recommends to the State Government to make immediate necessary arrangements for the regular adequate supply of drinking water (sweet) in the drought and backward areas of District Mahendergarh.

राव बंसी सिंह(अठेली): अध्यक्ष महोदय, आज जो रैजोल्यू इन सदन में लाया गया है, यह स्वीट वॉटर मुहैया करने के बारे में है। मुनश्य मात्र या प्राणी मात्र के लिए मेन तीन जरूरी चीजें हैं और मीठी पानी उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैंने इस मीठे पानी के बारे में ही आज सदन के सामने एक रैजोल्यू इन रखा है कि जिस इलाके को आज तक मीठा पानी नहीं मिल सका है, उसे मुहैया करने के लिए प्रबंध किए जाएं। आज तक भी इस इलाके के लोग खारा पानी पीते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इस रैजोल्यू इन के बारे में बताऊंगा। मैं यह मानता हूँ कि आज भी सारे हरियाणा के अंदर

हर डिस्ट्रीक्ट के अंदर बहुत से गांवों में खारा पानी है लेकिन सरकारी आंकड़ों को देखते हुए मैं आपको यह महसूस कराऊंगा कि डिस्ट्रीक्ट महेन्द्रगढ़ के अंदर आज की तारीख तक भी सबसे ज्यादा गांवों के अंदर खारा पानी है। **(इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुईं)** डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं आपके सामने कुछ फिगरज़ रखना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रीक्ट के कितने गांवों में अभी भी खारा पानी है। हमारे इरीगे एन एण्ड पावर मिनिस्टर साहब ने जो आंकड़े दिए हैं मैं वही आपके सामने पे टा करना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा था कि अम्बाला के अंदर 554 गांव है, डिस्ट्रीक्ट भिवानी के अंदर 489 गांव है, डिस्ट्रीक्ट गुडगांव के अंदर 441 गांव है, डिस्ट्रीक्ट हिसार के अंदर 609 गांव है, डिस्ट्रीक्ट जींद के अंदर 276 गांव हैं, करनाल डिस्ट्रीक्ट के अंदर 40 गांव हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर 141 गांव हैं, डिस्ट्रीक्ट सोनीपत में 246 गांव हैं और डिस्ट्रीक्ट महेन्द्रगढ़ के अंदर 623 गांव हैं जहां पर कि खारा पानी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस गिनती के अंदर सिर्फ एक महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रीक्ट ही है जिसके गांवों की गिनती दूसरे जिलों की निस्बत बहुत ज्यादा है। इस बारे में एक बात यह है कि डिस्ट्रीक्ट हिसार जिसके आंकड़े कुछ ज्यादा हैं, उससे डिस्ट्रीक्ट महेन्द्रगढ़ बहुत छोटा डिस्ट्रीक्ट है। जो मैंने 623 डिस्ट्रीक्ट महेन्द्रगढ़ के गांव बताये हैं, अगर हम उनमें रहने वाले पापुले टा का ख्याल करेंगे तो भी हम यह महसूस करेंगे कि पापुले टा के मुताबिक भी जिला महेन्द्रगढ़ के अंदर सारी स्टेट के मुकाबले में ज्यादा खारा पानी है। इन आंकड़ों को देखते हुए मैं यह समझता हूँ कि इस जिले के इलाके में जहां पर खारा पानी है, मीठा पानी देने के लिए टाप प्रौयरिटी दी जाए, बाकी जिलों की निस्बत इस जिले को टाप प्रौयरिटी दी जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस जिले को क्यों टाप प्रौयरिटी दी जाने की बात मैं करता हूं? दूसरे जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट गुडगांव है, रोहतक जिला है, करनाल है, अम्बाला है, मेरे कहने का मतलब यह है कि सारी स्टेट के अंदर लगभग सब जिलों में कैनाल का पानी अवेलेबल हैं। इन जिलों के जिन गावों के अंदर खारा पानी है, उन गावों के नजदीक से नहरें निकाली गयी है और वहां जोहड और तालाब बन गए हैं। उन जोहडो और तालाबों के अंदर या तो नहर का पानी डाला जा रहा है या फिर उसके अंदर कुएं खोद लिए जाते है और या फिर नहर का पानी पीनकके काम में लाया जाता है। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, बदकिस्मती से उस इलाके में आज तक भी कोई नहर नहीं ले जाई गई। आज तक भी उस इलाके के अंदर पीने के लिए मीठा पानी नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह अर्ज करुंगा कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ भी हमारी हरियाणा स्टेट का ही एक पार्ट है, उसे निगलैक्ट नहीं किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ के इन गावों में जो लोग रहते हैं, वहां पर बारि । बिल्कुल नहीं है। वहां पर जोहड तालाबों का पानी बिल्कुल सूख चूका है। मैं आपको यह बात बिल्कुल सच कह रहा हूं कि अगर बिजली का प्रोविजन न हो तो उनके प ु प्यास के कारण मर जाएं। मैं इस सरकार का भुकगुजार हूं कि हरियाणा स्टेट के अंदर बिजली गई और डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ के भी एक एक गांव में बिजली पहुंची जिससे खारे पानी ही सही, हम प ुओं को पिला तो सके। डिप्टी स्पीकर साहबा, मैं आपको क्या बताऊं, सारा हाउस इस बात पर हंसेगा यदि इन गावों में किसी के घर मेहमान आ जाता है तो वे उसे दूसरा पानी पिलाते हैं। वहां पर पानी के दो मटके

रखते है। एक में तो खारा पानी और दूसरे में मीठा पानी होता है। जब कोई मेहमान आता है तो वे कह देते है कि बटेंऊ वाला पानी लाकर पिलाओ। जो पानी तीन-चार मील से वे लाते हैं, उसको मेहमानो के लिए इस्तेमाल करते हैं।

आज उन हालात को देखते हुए वहां के लोग यह अंदाजा लगाते है कि जब दे 1 स्वतंत्र हो चुका है, गुलामी खत्म हो चुकी है और आज हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर सब से अधिक तरक्की कर रहा है, सब से ज्यादा हरियाणा का नाम है तब क्या कारण है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या वहां के लोग आज भी यह समझें कि विदेशी हकूमत है और इसलिए उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले तीन-चार साल के अंदर कुछ गांवों की वॉटर सप्लाई स्कीमज़ की तरफ ध्यान दिया लेकिन मैं यह कहूंगा जिन इलाकों का इस प्रस्ताव में जिक्र है वहां पीने के पानी की हालत बहुत ही खराब है। मैं सदन का ध्यान उन इलाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनके अंदर खारा पानी है और दूसरी तरफ जहां नहर है और उस इलाके के लिए जो स्कीम है, मैं यह नहीं कहता की उनको बंद कर दिया जाए, उनको कुछ दिनों के लिए स्लो-डाउन कर दिया जाए, कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए और टाप-प्रोयोरैटी उन इलाकों को दी जाए जहां पानी की बहुत अधिक तकलीफ है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस इलाके के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि इस इलाके के लोगो का यही कसूर है कि जिस समय दे 1 गुलाम था, अंग्रेजो का राज्य था, उस इलाके के वीरो ने 1857 की आजादी की लड़ाई के अंदर लड़ाई लड़ी, अंग्रेजो के खिलाफ वे लोग लडे। उस समय जो उस इलाके के बहादुर नौजवान थे वे सब के सब मातृभूमि

की रक्षा करने में काम आए। आजादी से पहले इस इलाके को उनके साथ जोड़ दिया जिन्होंने 1857 की जंगे-आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया था क्योंकि अंग्रेजों को भय था कि अगर इस इलाके के लोगों की इकनामिक हालत अच्छी हो जाएगी तो यह लोग अंग्रेजों को हकूमत नहीं करने देंगे। दे 1 की आजादी के लिए लड़ने के कारण ही उनकी तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन इलाकों को बैकवर्ड रखा। आखिर दे 1 आजाद हुआ और आजादी मिलने पर वहाँ के निवासियों ने सोचा कि अब हमारी सरकार है भायद भगवान हमारे लिए अमृत के रूप में बनाकर भेज दें। लेकिन आजादी के बाद भी उन गावों को पानी नहीं पहुँचा। आप समझ सकते हैं कि वहाँ के रहने वाले भी क्या महसूस करते होंगे। जब पैप्सू बना तो हमारे इलाके की नुमाइंदगी एक बहुतही सज्जन व्यक्ति करते थे। उन्होंने समय समय पर इस इलाके की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया लेकिन उस टाईम पैप्सू में हमारा अधिक बहुमत न होने के कारण हमारे साथ सौतेला सलूक किया गया। उसके बाद पंजाब बना और पंजाब के चीफ मिनीस्टर प्रताप सिंह कैरों बने। लेकिन उस वक्त भी हमारी बदकिस्मती रही कि जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करते थे उनका प्रताप सिंह कैरों के साथ टकराव था। वे किसी और इलाके में पानी ले जाना चाहते थे और इसी टकराव के कारण इस इलाके को नुकसान उठाना पड़ा और यह इलाका इग्नोर किया गया। आखिर उसके बाद पंजाब दो भागों में बंट गया और हरियाण बन गया। हरियाणा बनने के बाद कांग्रेस सरकार आई और पंडित भगवत दयाल चीफ मिनिस्टर बने लेकिन उस वक्त भी इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद उस इलाके के रहने वालों का समय आया जो आठ नौ महीने का समय

था और उस इलाके का आदमी स्टेट का चीफ मिनीस्ट बना लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस टाईम स्थाई गवर्नमेंट न बन पाई और उस इलाके की ओर वह ध्यान नहीं दे पाई। आज जो सरकार है वह पूरे बहुमत में है, मैजोरिटी में है चाहे जो कानून पास कर सकती है। उस इलाके के लोगों कि सरकार के सामने यह मांग है कि उनको पानी दिया जाए। आज तक उनके पास पीने का पानी नहीं है जो जिंदगी के लिए सब से जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से यह रिकवैस्ट करूंगा कि उस इलाके की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए और डिवैलपड इलाको में जो दूसरी स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमो को स्लो-डाउन करके इस इलाके को टाप-प्रायोरैटी दें। इस इलाके को पीने का पानी मुहैया किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारी यह भावना नहीं है कि दूसरी इलाके की तरक्की को रोका जाए। इस स्टेट के अंदर दूसरे जिले हैं मिसाल के तौर पर रोहतक हैं। पंजाब में चौधरी छोटूराम जो रोहतक के थे, को नुमायंदगी मिली और उनकी नुमायंदगी से रोहतक को बहुत फायदा पहुंचा। उस इलाके में जो नहरो का जाल बिछा है वह उनकी नुमायंदगी के कारण से ही है ओर उनकी नुमायंदगी से उस इलाके की मदद की। इसी तरह से दूसरे डिस्ट्रीक्ट हैं उनके अंदर भी इसी तरीके से काम हो रहा है। भिवानी के अंदर कोई काम होता है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे कोई दुख नहीं है कि वहां क्यों काम हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रीक्ट भिवानी में जो लोहारु और तो गाम का इलाका है वह सारा इलाका हमारे जैसा ही है। वह हमारे पडोस में है। उनकी हालत हमारे से भी बुरी थी। इसलिए हमें कोई दुख नहीं है। कि वहां पानी क्यों पहुंचा है? हम तो जो हमारा हक है मंत्री महोदय से उसकी डिमांड करते हैं। इस रेजोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए इस साल यानी

1974-75 में डिवाइलपड एरियाजके लिए वॉटर सप्लाई कीजो स्कीमें चल रही है उनको स्लो डाउन करके ज्यादा फंडज उन इलाको को दिए जाएं जहां खारा पानी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह इलाका हमे आपकी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने नौजवानो की कुर्बानी देता रहा है। चीन की जब लडाई हुई, आप इतिहास उठाकर देख लें सब से ज्यादा कुर्बानी इस इलाके के लोगो ने की। इसके बाद पाकिस्तान से दो लडाईयो हुई, इन दोनों लडाईयो में भी इसी इलाके के लोगो कि अधिक कुर्बानी है। पाकिस्तान के साथ जो दूसरी लडाई हुई उसमें हमारे यहां के एक नौजवान जिसका नाम बबरु बान था, जो कि नेवी में था, उसने अपनी बहादुरी से एक मिसाल कायम कर दी। उसने पाकिस्तान के जहाज के अंदर घुसकर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान की फतेह हुई। जिस सूखे इलाके के नौजवान इतने बहादूर हो और जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानी की हो क्या आज उनको इतना भी हक नहीं कि वे पीने के पानी की डिमांड कर सकें? इसलिए मैं आपके थ्रू मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि इस रैजोल्यूशन को यूनानी मसली सारा हाउस पार करे और ड्राट अफैक्टिव एरियाज के लिए पानी की जो स्कीमज है और 1 करोड 44 लाख रुपया जो सेंटर की तरफ से ऐलोकैट हुआ है उसमें सब से ज्यादा हम इस इलाके को मिलना चाहिए क्योंकि इनका सब से ज्यादा हम बनता है। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

चौधरी फूल सिंह कटारिया (साल्हावास-अनुसूचित जाति):

उपाध्यक्ष महोदया, आज जो रैजोल्यूशन राव बंसी सिंह जी ने रखा है मैं इसकी पूरजोर हिमायत करता हूं। हिमायत मैं इसलिए करता हूं कि ये भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं

लेकिन इन्होंने थोड़ी सी यह भूल कर दी इन्होंने इस रेजोल्यूशन में झज्जर और नाहड तहसीलो के नाम नहीं दिए। इन्होंने कहा कि हमारा महेन्द्रगढ का जिला एक बहादूरों का जिला है लेकिन मैं हाउस को यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि झज्जर तहसील ऐसी बहादूर तहसील है कि उसके मुकाबले में कोई तहसील या जिला इतना बहादूर नहीं है। झज्जर तहसील में सब से ज्यादा फौजी हैं। मैं आपको बता दूँ कि सारे हरियाणा में पचास हजार फौजी हैं जिनमें से दस हजार इस हलके के फौजी हैं। मेरे हलके में एक कोसली गांव है वहां अभी भी तीन-चार लाख रुपया महीना पैसा आता है फौजियों को। मेरे हलके में आप जा कर देखें कि एक एक घर में तीन तीन चार चार कैप्टन और मेजर मिलेंगे। मैं यह नहीं कहता कि राव बंसी सिंह ने ठीक नहीं कहा लेकिन मैं तो यह बताना चाहता हूँ कि इसमें झज्जर तहसील का नाम भी आना चाहिए। झज्जर तहसील ने बहुत बहादूरी के काम किए हैं। 1857 में यहां का नवाब फांसी लगा जो कि काबिले तारीफ है। यह इलाका भी तो इनके साथ ही है। अंग्रेजो ने अपने वक्त में इन इलाको की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जो नाहड तहसील का इलाका है उस जगह पर पानी कडवा है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। रोहतक जिले में 431 गांव ऐसे हैं जहां का पानी खारा है लेकिन झज्जर तहसील के कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पानी की चाय भी नहीं बनाई जा सकती। वहां पर लोग हर साल कच्चे कुएं खोदते हैं। उनको पानी की इतनी तकलीफ है कि भायद ही हरियाणा में इतनी तकलीफ कहीं और हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा आपने भायद वह इलाका देखा नहीं होगा, अगर आप उस इलाके को एक बार देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वहां के लोगो की क्या हालत है।

मंत्री और मुख्य मंत्री महोदया का मैं म आकूर हूं कि उन्होंने तीन स्कीमें बना रखी है। जिनमें से एक स्कीम “C” पर काम चल रहा है। यह स्कीम 1967 से चली थी। एक स्कीम के तहत 15-16 गावों में पानी पहुंचता है लेकिन वहां के लोगों ने मिल कर एप्रोच करी कि इस स्कीम को चले 5-6 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा है और न ही बाकी की दो स्कीमों का अभी काम पूरा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि पब्लिक हेल्थ वाले काबिल नहीं हैं, वे बड़े अच्छे काबिल अफसर हैं, वहां पर आते हैं लोगों की तकलीफो को सुनते हैं, मैं उनकी पूरी तारीफ करा हूं लेकिन वे कहते हैं कि हमारी मजबूरी है वह हमारे पास फंड्ज की कमी है। जब गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि वह सब से पहले पीने के पानी की तरफ तवज्जोह देगी तो गवर्नमेंट से अर्ज करुंगा कि उसे सबसे पहले उन इलाको की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जहां पानी नहीं है। जैसे कि झज्जर तहसील और नाहड सब-तहसील के इलाके हैं। गवर्नमेंट ने यह जो स्कीम बनाई है इसमें गांव वालो को भी कुछ हिस्सा देना होता है तो मेरे इलाके में कुछ गांव ऐसे है जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और वे यह हिस्सा नहीं दे सकते। तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करुंगा कि ऐसे इलाके जिनका पानी खराब है ओर जो गरीब है वहां पर पीने का पानी का बिना पैसे लिए जल्दी इंतजाम किया जाए। 5-7 गांव तो ऐसे हैं कि जहां स्कीम बिल्कुल तैयार पडी है लेकिन पैसे न होने की वजह से वही रुकी पडी है। जिन इलाको में पानी बहुत ज्यादा खराब है जहां के पानी से चाय भी नहीं बन सकती वहां पर किसी का कोई रि तेदार तक नहीं जाता क्योंकि वह जानता है कि वहां पर जाकर तकलीफ उठानी पडेगी। इसलिए सरकार से मेरी फिर प्रार्थना है कि जिन

इलाको में पानी खराब है उनके लिए जल्द से जल्द इंतजाम किया जाना चाहिए। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी मनफूल सिंह पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, आप कुर्सी पर विराजमान हैं और आप भी उसी हलके से ताल्लुक रखते हैं जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। आपको तो भली भांती पता है कि उस इलाके का क्या हाल है। चूंकि अब आप कुर्सी पर विराजमान हैं इसलिए मैं आपसे और भी उम्मीद रखता हूँ कि आप इस तरफ और भी गौर करवाएंगे। जिन गावों की स्कीम बन चुकी है उनमें कुछ गाव हैं जैसे कोका, कुलाना और डाकना भायद इनके पैसे जमा हो गए हैं जो ढाकना गांव है वहां के सेठ ने पैसे जमा करवा दिये हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन गावों ने अपने हिस्से के पैसे जमा करवा दिये हैं उन पर तो जल्द से जल्द काम भुरु करवा दिया जाए। इसके अलावा मैं साल्हावास के हलके की बात करता हूँ इसमें भी कई गांव हैं जैसे खानपुर, बहाला और नया गांव। तो ये गांव ऐसे हैं जिनका पानी बिल्कुल खराब है। इनके बारे में मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि ये गांव पानी न होने की वजह से इतने तंग हैं कि कुछ कहने से बाहर हैं। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो गांव स्कीम में शामिल हैं उनमें वह जल्द से जल्द पानी पहुंचाने की कृपा करें। और चेयरमैन साहब, कई गांव मेरे हलके में ऐसे हैं जहां स्कीम चली हुई है लेकिन वहां पानी नहीं है जैसे वहां एक धरोड गांव है उसमें दो साल से पानी की स्कीम चली हुई है लेकिन पिछले दो महीनों से वहां से लोगों की शिकायत है कि वहां पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा एक बात और है कि जहां भी हरिजनो के मुहल्ले हैं वहां पानी के नलके नहीं लगे हुए हैं और गवर्नमेंट की

तरफ से यह कहा जाता है कि जहां हरिजनो के मुहल्ले हो वहां नलके जरूर लगाए जाए। मैं अपने इलाके की ही नहीं कहता सभी के लिए कह रहा हूं। जैसे खरखौदा एक बहुत बडा गांव है (11:30 बजे) वहां हरिजनो के मुहल्ले मे पानी के नलके नहीं है। मैं नाहड की बाबत भी कहता हूं कि वहां अब पानी तो आ गया है लेकिन हरिजनो के महल्लो में नल नहीं लगाए गए। स्पीकर साहब ये आदमी हमे गा कांग्रेस का साथ देते है लेकिन चूंकि वे गरीब हैं इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन इन के मुकाबले में जो बडे बडे अमीर आदमी होते हैं वे फायदा उठा जाते हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार से निवेदन करुंगा कि जहां जहां पानी नहीं है उन गावों में पीने का पानी दिया जाए और जिन गावों में पानी दे दिया गया है वहां पर हरिजनो के मुहल्ले में नलके जरूर लगवाये जाएं ताकि उनको पानी की आसानी के साथ सुविधा प्राप्त हो सके। बस मैं आप के द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता था और मुझे आ गा है कि हमारी सरकार इन बातों को ध्यान में रख कर सारा प्रबंध करेगी।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सिर्फ मिनिस्टर महोदय की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि कर्नल महा सिंह जी दो गांव में गए थे खेडी और खातीबास और वह अपने वक्तो की चेयरमैन साहब एक स्कीम थी जिस को वह जिन्दा कर आए थे और उन्होंने वायदा किया था कि वहां पानी का जल्दी इंतजाम हो जाएगा। इस बात को आज सवा दो साल हो गया है। मैं यह चाहता हूं कि और किसी का वायदा तो बे तक कच्चा हो जाए लेकिन कर्नल महा सिंह का फौजी वायदा कैसे कच्चा हो जाए तो वह वायदा पुरा होना चाहिए। इस के अलावा चेयरमैन साहब गूढा

और घौर दो गांव हैं उन दोनों गावों का पानी भी उतना ही खराब है जितना कि खेडी और खातीबास का है और वह दोनों गांव कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए इसी स्कीम का पार्ट अगर गूढा और घौर को भी बना लिया जाए तो इन चारों गांवों को एक ही जगह पानी मिल सकता है। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि गूढा और घौर इन दो गावों को भी स्कीम में शामिल कर लिया जाए। अगर इतना ही हो जाए मेरे हलके में तो बहुत है। बस मैं इतना ही अर्ज करना चाहता था।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): चेयरमैन साहब, सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्री बंसी सिंह और राव दलीप सिंह जी लाए हैं। इस के लिए उनको मुबारिकबाद देता हूँ। इस रैजोल्यूशन में यदि वे महेन्द्रगढ़ के साथ साथ हिसार जिला का भी नाम जोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि राव बंसी सिंह जी ने आंकड़े देते वक्त बताया कि हिसार जिला में सब से ज्यादा बैकिंग वाटर है। तो यह स्पीकर साहब आज की बात नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में जो कि यह क्लेम करते थे कि हम हिन्दोस्तान को बहुत आगे ले जा रहे हैं उस वक्त भी हमारे यहां पीने के पानी की गंभीर समस्या थी। मेरे जिला में ऐसे इलाके थे जहां पर पानी के पानी को रातान होता था। चेयरमैन साहब, अडलट्रेन आपने दूध की, घी की या दूसरी खाने की चीजों की तो सुनी होगी लेकिन मेरे जिले में पीने के पानी की अडलट्रेन होती थी। भाखडा की नहर आने के बाद वहां कुछ राहत मिली है वरना पहले जब हम रेल गाडी पर सफर करते थे, जिस स्टेशन पर गाडी रुक जाती थी लोग सैंकड़ों की तादात में मटके लेकर इंजन की तरफ पहुंच जाते थे और ड्राइवर के मुंह की तरफ

देखते थे कि इन को कुछ पीने का पानी मिल जाए। चेयरमैन साहब, एक बार भोलाभाई देसाई ने सेंट्रल असैम्बली में बोलते हुए अंग्रेजों को चैलेंज किया था कि तुम अपने राज में लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं कर सकते। उस वक्त तो गैर हकूमत थी और गुलामी का जमाना था लेकिन जिस वक्त दे 1 आजाद हुआ तो हम लोगों ने सोचा, चूंकि अब मुल्क अजाद हो चुका है अब हमें पीने का पानी मुहैया किया जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब, 1952 तक हरियाणा ने और हिसार में खासतौर पर पीने का पानी देने की कोई स्कीम नहीं बनाई गई, सन् 1952 के बाद जब ज्वायंट पंजाब में स्कीम बनी तो सन् 1958 तक कुल 203 गावों में ही पीने के पानी का इंतजाम किया गया, यानि एक साल में मुक्ति काल से कोई 12 गावों कवर होते हैं। जिस वक्त चौधरी बंसी लाल जी ने मुख्य मंत्री का कार्य भार सम्भाला यह जो उन के अहद का 6 साल का पीरियड आज तक गुंजरा है मैं इसे अगर यह कहूँ कि यह गोल्डन पीरियड आफ द हिस्ट्री आफ हरियाणा है तो भाग्यद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। सब से पहले चौधरी बंसी लाल जी ने इस बात की और खास तौर से ध्यान दिया और देना भी जरूरी था क्योंकि वह खुद ऐसे इलाके के रहने वाले थे जहां पर पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या थी। चेयरमैन साहब इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चौधरी बंसी लाल जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पीने के पानी देने की तरफ ध्यान दिया गया है लेकिन इस के बावजूद भी पीने का पानी दस्तयाब करने की तरफ जितनी तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं बढ़ाया गया। तमाम हरियाणा के लिए 1.75 करोड़ का कुल बजट इस साल के लिए मुहैया किया गया था। ठीक है इस में ज्यादा हिस्सा जो कि 1.44 करोड़

रुपया देहातों को पानी देने के लिए रखा गया है और इस में 100 देहातो में पानी देने की स्कीम पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह बहुत थोड़ी रकम है। यहां पर फाईनैस पार्सल्टी की बात हर वक्त की जाती है। मैं आप की मारफत चेयरमैन साहब यही कहूंगा कि सरकार को अगर कोई स्पै ल सैंस लगाकर भी पीने का पानी का इन्तजाम करना पड़े तो यह जल्दी से जल्दी करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस में इस हाउस के किसी मेंबर को भी एतराज नहीं होना चाहिए। यहां पर क्वै चन आवर में ओपोजी न वाले एक भाई ने कहा था कि जिस स्पीड के साथ गवर्नमेंट इस काम को करना चाहती है, जितनी थोड़ी रकम प्रोवाईड की गई है, उस के हिसाब से तो भायद पीने का पानी तमाम देहातों को देने के लिए 50 साल लग जाएं। तो मैं अपनी सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या 50 साल तक हम इन्तजार कर सकते हैं, क्या पीने के पानी के लिए हमें और 50 साल इन्तजार करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब पानी और हवा के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है यह सब मुफ्त मिल सकते हैं। तो पानी जिस के लिए सब का हक है कि मुफ्त मिलना चाहिए उसके लिए हमें 50 साल और इन्तजार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यह एक आजाद मुल्क के लिए बायसेफ़ख़ बात नहीं है। इसलिए चाहे आप को कुछ भी करना पड़े, आप को गवर्नमेंट आफ इंडिया पर जरूर प्रै र डालना चाहिए, आपको पीने के पानी का प्रबंध जल्द से जल्द करना चाहिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ हाथ न बंटाते हो। हिन्दोस्तां में दो ही तो प्रदेश हैं जिन की ओर सारा हिन्दोस्तां देखता है। तो चेयरमैन साहब पीने के पानी की जो आज समस्या है इसकी तरफ सरकार को

खास ध्यान देना चाहिए। मैं अब ज्यादा न कहता हुआ चंद बातें अपने हलके के बारे में भी कहना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा हलका अर्बन कहलाता है लेकिन कुछ देहात उसके साथ जुड़े हुए हैं और मेरे हलके में दो देहात खास तौर पर ऐसे हैं जहां पानी ब्रेकिंग है और जोहड के किनारे जो कुआं है उससे ही गांव की सारी आबादी पानी लेती है लेकिन उस में पानी पर्याप्त नहीं है। ये दो गांव हैं तलवंडी राणा और गंगवा। गर्मियों में खास तौर पर कुएं का पानी सूख जाता है और जब औरतें कुएं पर पानी लेने जाती हैं तो पानी की कमी की वजह से उनमें आपस में झगड़े होते हैं। एक बात और है जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह पालिसी की बात है लेकिन पालिसी भी तो सरकार ही बनाती है और हालात के मुताबिक वह बदल भी सकती है। वह पालिसी यह है कि जब तक बैनिफिटरी भोयर गांव वालों की तरफ से जमा न कराया जाए वाटर सप्लाई स्कीम लागू नहीं की जा सकती। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। चेयरमैन साहब, यह ठीक है कि मैं अरबन हलके को रिप्रैजेंट करता हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों की बातें सरकार के ध्यान में नहीं ला सकता। जब भाहर के अंदर वाटर सप्लाई स्कीम बनती है तो भाहर के जराये तो बहुत वसीह देते हैं वह पैसे दे सकते हैं और म्युनिसिपैल्टी रुपया मुहैया कर सकती है। लेकिन अभी तक देहात के पास इतने जरिये नहीं हैं और खास तौर पर उन देहातों के पास जिनकी पंचायत की आमदनी बहुत थोड़ी है। इसलिए ऐसे केसिज के बारे में ध्यान दिलान जरूरी है। मिसाल के तौर पर हमारा तलवंडी राणा गांव है उसकी पंचायत की कोई आमदनी नहीं है क्योंकि उनके पास कामॅनलैंड नहीं है जिससे आमदनी हो सके और ऐसे गांव जिनके पास पैसा नहीं है वा बैनिफिटरी भोयर नहीं दे

सकते और यह दिये बगैर उनके लिए वाटर सप्लाई स्कीम लागू नहीं हो सकती। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह चीज हटनी चाहिए और जिन देहात के अंदर कुओं में पानी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है सूख जाता है वहां सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी नहरी पानी के जरिए पीने का पानी दिया जाना चाहिए और जिन देहात के पास आमदनी के साधन नहीं जिनकी माली हालत मजबूत नहीं कि बैनिफि तारी भोयर दे सकें उनका बैनिफि तारी भोयर माफ करके वहां पीने का पानी दिया जाए और यह स्कीम लागू की जाए। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इन दो गांव की तरफ दिलाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों गांव में पानी की स्कीम जल्दी से जल्दी लागू की जायेगी। इन भाब्डों के साथ मैं इस प्रस्ताव की हिमायत करता हूँ और चाहता हूँ कि इसके साथ ज़िला हिसार का नाम भी जोड दिया जाए।

श्रीमती लज्जा रानी (बाधडा): चेयरमैन साहब, इस प्रस्ताव पर बोलते हुए राव बंसी जी ने और कटारिया जी ने फौजियों की बात करके उन इलाको के लिए पानी की मांग की है और मैं भी इस प्रस्ताव पर मेरा हलका फौजी होने के नाते बोलना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गवासी पजिदेव मेजर साहब ने दादरी के अंदर जनरल हरबख्भा सिंह जी के समय में फौजी दफ्तर भर्ती के लिए खुलवाया था। उसकी अब क्या हालत है उस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जब कोई बच्चा देा की सेवा के लिए देा की रक्षा के लिए अपनी छाती पर गोली खाने के लिए फौजी दफ्तर में जाता है तो वह वहां तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वा पांच सौ रुपये न दे दे या कम से कम चार सेर घी न दे दे। कितनी हैरानी की बात है कि यह किए

बिना बगैर कोई भी नौजवान वहां भर्ती नहीं हो सकता। हम अपने इलाके की फौजी होने के नाते बड़ी तारीफ करते हैं लेकिन वहां यह हालत हो रही है कि कोई देा की रक्षा के लिए अपनी छाती में गोली खाने के लिए भी बिना पैसे दिए दाखिल नहीं हो सकता। बाकी पानी जो हालत वहां पर है और मैं आता करती हूं कि हमारे महेन्द्रगढ को कम से कम फौजी होने के नाते पीने के पानी के मामले में प्रैफरेंस दी जाए और इन अलफाज के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री के० एन० गुलाटी(फरीदाबाद): चेयरमैन साहब, मैं इस प्रस्ताव की ताईद करने के लिए खडा हुआ हूं और मैं इसकी पूरजोर ताईद करता हूं ओर इस बारे में अपने ख्यालात सदन में पेा करना चाहता हूं। बडे अफसोस की बात है कि 27 साल की आजादी के बाद भी हमारे यह हालत है कि बहुत सारे गांव में पीने का पानी भी हम नहीं दे पायें है। मीठा पानी जिंदगी की सब से जरुरी चीज है और सरकार को बड़ी तेजी के साथ इस तरफ कदम उठाने चाहिए। मैं हरियाणा सरकार को और इस सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा बहुत तेजी के साथ तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और प्रदेा के अंदर काफी डिवैलपमेंट के काम हुए हैं। रोडज, बिजली, आबपााी और दूसरे हम मामले में हरियाणा तरक्की के रास्ते पा आगे बढा है जिसके लिए हरियाणा निवासियों को फख है। लेकिन मीठे पानी के मामला में काफी दिक्कत है। यह ठीक है कि समय के अनुसार यह काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है और काफी गांव को मीठा पानी दिया भी गया है और दिया जा रहा है लेकिन जो गांधी जी का स्वप्न था कि आजाद भारत में हर इंसान को कम से कम जरुरियाते जिंदगी मुहैया हो वह पूरा नहीं हुआ ओर उस

तरफ हरियाणा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और गांधी जी के स्वप्न की याद दिलाता हूं। मीठापानी हर इंसान के लिए चाहे वह भाहर में रहता है चाहे देहात में रहता है जरूरी चीज है और यक कै । प्रोग्राम बना कर चाहे सडको बिजली वगैरा के काम पीछे कर दिये जाएं लेकिन मीठा पानी हर इंसान को जल्दी दिया जाए। मैं मानता हूं कि सूखे और बैकवर्ड एरियाज को प्रैफरेंस दी जाए लेकिन इसके साथ साथ दूसरे इलाको के लिए भी जरूरी है कि उनको मीठा पानी दिया जाए। एक बात मैं सुझाव के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे भारत में हर साल बहुत पजड्ज आते हैं और करोडो का नुकसान होता है लेकिन आज तक कोई ऐसी प्लानिंग नही बनी कि इस पानी को काम में लाया जाए। मिसाल के तौर पर असम में हस साल पलडज आते हैं और भारी नुकसान होता है। सारी स्टेट्स कुआर्डिनेशन करके इस पलड वाटर को कंट्रोल करके आबपा नि के लिए फिल्टर करके मीठे पानी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और जहां मीठे पानी है लेकिन वह वेस्ट होता है। उसकी वैस्टेज चैक की जाए तो यह मीठा पानी दूसरे कमी वाले इलाको में दिया जा सकता है। मैं यह भी महसूस करता हू कि आफ्फिियल्ज की तरफ से मीठा पानी देने के मामला में गलत प्लानिंग भी चलती है और कुछ करण भी चलती है। मैं अफसरान से और चीफ इंजिनियर साहब से कहना चाहता हूं कि वह इस करैण को चैक करें और पानी के इस्तेमाल के बारे में सही प्लानिंग बनाये ताकि पानी वेस्ट न हो। यह जो कंट्रैक्टर्ज पूल सिस्टम है इस में यह होता है कि मैटीरियल फस्ट क्लास लगना चाहिए वहां थर्ड क्लास मैटीरियल लगता है और जहां सौ बोरियां सीमेंट दी जाती है वहां दस लगाई जाती है। यह बात

अफसरान के नोटिस में भी होगी। फिर ट्यूबवैल्ज खोदे जाते है तो उस में यह होता है कि पचास फिसदी खोदने के बाद बंद कर दिये जाते है कि पानी नही मिला। इस में ऐसी प्लानिंग हो कि पहले बकायदा चैक करने के बाद खुदाई कि जाए कि पानी मिलेगा या नही मिलेगा। फिर आप देखें कि अगर ट्यूबवैल सरकारी तौर पर खोदा जाए तो उस पर एक लाख लागत आती है लेकिन अगर वही ट्यूबवैल प्राईवेट एजेंसी से खुदवाया जाए तो पचास हजार लगते हैं यानि आधा खर्च आता है। तो मैं अर्ज करता हूं कि अगर प्राईवेट एजेंसी आधा खर्च करके उसे बना सकती है तो आफ्ी तल एजेंसी को भी

चौधरी पीर चंद: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, आठ ही मैम्बर बैठै है और कोरम नही है.....

श्री सभापति: कोरम पूरा है, आठ का ही होता है।

श्री के० एन० गुलाटी(फरीदाबाद): तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मीठा पानी देने के मामला में प्रापॅर प्लानिंग की जाये और इस करप्ान को खत्म किया जाये क्योंकि यह जनता का पैसा है इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। पैसा सही ढंग से इस्तेमाल हो तो चेयरमैन साहब, आप बताएं पानी कैसे जल्दी नही दिया जा सकता। जो इस पर खर्च होता है उस सारे एक्सपेंडीचर को चैक करना निहायत जरुरी है। मैं इसी आइटम पर बोल रहा हूं कि आफिसिज के अंदर जब कांट्रक्टर को चेक किया जाता है तो 10 परसेंट कै र रख लिया जाता है। यह जो सिस्टम चल रहा है इसको ओवरहाल किया जाए तभी जल्दी पानी मिल सकेगा। चेयरमैन साहब, मीठे पानी का रैजोल्यूान हमारे सामने है। पानी का ताल्लुक हमारी सेहत के साथ है, सैनिटेान के साथ है।

अगर हम पानी का कै 1 प्रोग्राम बनाकर दे देंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हर हिंदूस्तानी की, हर हरियाणा वासी की सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि पानी के सैनीटे 1न के साथ गहरा ताल्लुक है। पानी न हो तो सैनीटे 1न, सिवरेज सिस्टम काम नहीं कर सकता, कुनैक 1न लेना ही फिजूल है। मैं थोडा सा फरीदाबाद की तरफ भी जाना चाहूंगा। मेरे इलाके में 109 गांव हैं। 109 देहातो में पानी की बहुत तकलीफ है। इनके साथ में भाहरी इलाके भी लगते हैं। वहां मीठे पानी की बहुत जरूरत है और मीठे पानी के ट्यूबवैल खोदे जाने चाहिए। जो ट्यूबवैल खुदे हुए है उन में पानी का जितना डिस्चार्ज होना चाहिए उतना नहीं है। यह भी गलत प्लानिंग के अंदर आ जाता है। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रैजोल्यू 1न हमारे सामने है यह बडा अहम है, इसकी तरफ सरकार को और खास तौर पर सैक्रेटरी साहिबान को जल्द तवज्जोह देनी चाहिए और एक कै 1 प्रोग्राम बनाकर मीठे पानी का इंतजाम करें। बे 1क ये प्रोयोरैटी सूखा ग्रस्त इलाको को दें, फिर बैकवर्ड एरियाज को दें और फिर इसके बाद सारे हरियाणा के अंदर कै 1-प्रोग्राम बनाकर इस समस्या को हल करने की को 1 1 करे। मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है।

राव अभय सिंह (रेवाडी): चेयरमैन साहब, आज इस सदन में राव बंसी सिंह और राव दलीप सिंह जी ने एक रैजोल्यू 1न द्वारा जिला महेन्द्रगढ के बैकवर्ड इलाको के लिए मीठा पानी देने के लिए गवर्नमेंट से मांग की है। जिस में हाउस को कहा गया कि इस रैजोल्यू 1न को मुंत्फिका तौर पर तारीफ करें और गवर्नमेंट को रिकमेंड करें। मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और अपने साथियों से, एम0 एल0 एज0 से हाउस को पुरजोर अपील करुंगा कि वे

इस रैजोल्यूशन की मुंत्फिका तौर पर तारीफ करें और गवर्नमेंट को रिकमेंड करें। चेयरमैन साहब, पीने के पानी का बहुत भारी मसला है। मुझे याद है कि सन 1952, जब युनियन पंजाब था ओर मैं पहली दफा पंजाब के सदन में चुन कर आया था। उस वक्त भी हम जोर लगा रहे थे कि इस इलाके को पीने का पानी मुहैया किया जाए। पहले रेवाडी तहसील गुडगांव में थी और महेन्द्रगढ पैप्सू में था। उस वक्त से मेरे साथी जोर लगा रहे थे कि रेवाडी तहसील खारी चक का इलाका है, वहां पर मीठा पानी दस्तयाब नहीं होता। हमने काफी जोर लगाया लेकिन कामयाब नहीं हुए, यह तो आपको पता ही है। चेयरमैन साहब, यूनियन पंजाब में हरियाणा के लोगो के साथ बेइंसाफी होती थी और यही वजह थी कि हरियाणा आज वजूद में आया, इसके बाद यह मसला जोर पकडता रहा और मैं समझता हूं कि जब से चौधरी बंसी लाल की हकूमत आई तो जिला महेन्द्रगढ में और रेवाडी तहसील में खास तौर पर काफी इलाको को पानी दिया गया। जो घरेना वाटर सप्लाई स्कीम, मसानी वाटर सप्लाई स्कीम तथा ढडोली वाटर सप्लाई स्कीम है इन तीनों से कम से कम 50-60 गावों को हमारी तहसील में पानी दिया गया। इसके बावजूद भी चेयरमैन साहब, आज महेन्द्रगढ जिले का बहुत सा इलाका खारा पानी का है। जो काम हुआ है वह काफी हुआ है लेकिन मसले को देखते हुए अभी बहुत पीछे हैं, काफी काम होना बाकी है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पीने का पानी बहुत दूर से लाना पडता है। जैसा कि राव बंसी सिंह ने कहा है ओर दूसरे साथियों ने कहा है कि यह इलाका ऐसा है जिसके देाभक्तो का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आपने सन् 1857 की स्थिती देखी होगी। मैं समझता हूं कि यह रैजोल्यूशन बडा अहम है

और वहां के गाव इस के लिए डिजर्व करते है कि मीठे पानी के लिए जल्दी से जल्दी इंतजाम किया जाए। जैन साहब ने अपनी स्पीच में फरमाया था और मैं भी इस बात को समझता हूं कि पीने का पानी के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने पैसा ऐलोकेट किया है वह बहुत कम है। इसी कमी के कारण जिला महेन्द्रगढ के इलाके में या दूसरे इलाकों में जहां पानी की कमी है, इतने कम रुपयों में पानी देने में बहुत अर्सा लगेगा। मेरी हाउस को ओर गवर्नमेंट को सजै ान है कि जैसे सडको और बिजली के लिए कै ा प्रोग्राम बनाया था, जैसे गुलाटी साहब ने कहा कि इसके लिए जब तक कै ा प्रोग्राम नही होगा, वार फुटिंग का काम नही होगा तब तक यह काम पूरा नही होने वाला। अगर होगा भी तो कम से कम 20-30 साल लग जाएंगे। सरका का या फरजेअलबीन है कि कम से कम लोगों को मीठा पानी जरूर दें। मीठे पानी के बारे में मेरे इलाके में भी काफी तकलीफ है जहां पर कि स्कीमें बनी हुई हैं। उन स्कीमो की तरफ भी मैं अपनी गवर्नमेंट का और अफसरान का ध्यान दिलाना चाहता हू। रेवाडी तहसील में जडथल वाटर सप्लाई स्कीम है जो मेरे इलाके के 50-60 गावों को कवर करती है और इन गावों में पानी की बडी तकलीफ है। इन के लिए गवर्नमेंट थोडा बहुत ही रुपया दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि वह नाकाफी है। डिपार्टमेंट को इन स्कीमो को जल्दी से जल्दी भुरु किया जाना चाहिए। दूसरी झावुबा सुलखा वाटर सप्लाई स्कीम है इसके लिए भी मैं सरकार से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। एक छोटी सी स्कीम मसानी वाटर सप्लाई स्कीम है। इस स्कीम को गांव ढंगरवास, फडेरी, रामगढ, भगवानपुर, टरकियावास और बुरानी तक एक्सटैंड कर दिया जाए। मैंने इस के बारे में चीफ दंजीनियर साहब से कहा था कि इन

तीन चार गांवों तक एक्सैंट कर दिया जाए। थोड़े से पैसों में ही डिपार्टमेंट इनको चालू कर सकता है। तो इसके लिए मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी इन गांवों को कम से कम पीने का पानी तो मिल जाए। इसके साथ ही मैं फिर हाउस के अपने साथियों से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस रैजोल्यूशन की वे मुतफिका तौर पर ताईद करें। कुछ साथियों ने कहा कि कुछ जिलों के इलाके ऐसे हैं जिनमें वाकई ही पानी की बहुत दिक्कत है। वे लगभग दो चार तहसीलें हैं। अगर इनका नाम भी इस रैजोल्यूशन के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके लिए भी मैं मुत्फिक हूँ।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। यह जो कानकोक्टिड भाब्द का प्रयोग किया है, इसको मैम्बर साहब को वापिस ले लेना चाहिए। यह भाब्द ठीक नहीं है।

श्री अमर सिंह: मैं इस भाब्द को विदड्रा करता हूँ। चेरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि 27 साल के अरसे में, जो बहादुर इलाका है जैसे महेन्द्रगढ, झज्जर, भिवानी और बवानी खेडा, और रुहनात के इलाके हैं जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी उनको पहले भी काफी सजा मिल चुकी है। ज्वायंट पंजाब में भी सजा मिली है लेकिन आज तो खुद अकिस्मती है इस इलाके की कि वहां का ही चीफ मिनिस्टर हैं। हमें इस बात को गौरव है उनका ध्यान उन टिब्बों पर पानी पहुंचाने का है लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि वार वेसिज़ पर इस बात को ले कर हर गांव को पीने का पानी और नहरी पानी पहुंचाया जाए। वे लोग आज भी जोहडो का पानी पीते हैं।

चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए सरकार से निवेदन करुंगा कि जो प्रस्ताव रखा है इसको पास किया जाये और प्राथमिकता दी जाये। जिस तरह से कै 1 प्रोग्राम से बिजली लगायी गई, जिस कै 1 प्रोग्राम से रोड्ज का इंतजाम किया गया उसी प्रकार से वाटर सप्लाई स्कीम चालू की जाये। इस स्कीम पर चाहे 75 करोड की बताए एक अरब रुपया खर्च हो। लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी सब से जरुरी चीज है। यह हिस्टोरिकल फ़ैक्ट है कि जब अमर सिंह राठौर ि 1कार खेलने गए हुए थे तो अजमल खां पानी की प्यास में तडप रहा था। उसने जब खान को तडपते हुए देखा तो उसने अपनी गागर से पानी पिलाया। जब अजमल खां हो 1 में आया तो उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करता हूं। जब भी कभी आप पर मुसीबत आएगी, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। यह एक हिस्टोरिकल फ़ैक्ट है कि जब अमर सिंह राठौर पर चढाई की गई उसी अजमल खां पठान ने वहां के उस वक्त के बाद 11ह का मुकाबला किया और अमर सिंह राठौर की जान बचायी। इसलिए पानी जैसी सस्ती चीज जो जिंदगी के लिए अमृत है का होना जरुरी है। चेयरमैन साहब, मैं इस रैज्योलू 1न की पूरजोर अल्फाज़ में हिमायत करता हूं। और आपके जरिए सदन से यह रिक्वैस्ट करुंगा कि यह एक जायज प्रस्ताव है, इस इलाके को प्राथमिकता दी जाये और यह मानकर सरकार को चलना चाहिए, यह मेरी गुजारि 1 है।

चौधरी मेहर चन्द (बडौपल): चेयरमैन साहब, राव बंसी सिंह जी और राव दलीप सिंहजी को जो नान-रैज्योल्यू 1न हाउस के ज़ेरे गौर है, वह एक बेसिक रिक्वायरमेंट आफ लाईफ के बारे में है। इस वास्ते मैं यह महसूस करता हूं कि इस रैज्योलू 1न पर किसी मजीद

डिबेट के, यूनेनीमसली फौरन पास किया जाये क्योंकि इस रैज्योलू इन पर मुखालिफत करने का तो कार्ड सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इसको होल-हर्टिडली स्पोर्ट करता हूँ। पीने के लिए पानी आबपा गी के लिए पानी एक जिंदगी है यह किसी को भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से पानी जिंदगी कायम रखने के लिए है इसी तरह से आबपा गी के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। अगर आबपा गी के लिए पानी नहीं है तो भी जिन्दगी खत्म हो जाती है क्योंकि फिर प्रोडक् इन का सवाल आ जाता है जिससे हम अपनी लाईफ को मैनटेन करते हैं। चेयरमैन साहब, इस फसिल्टी को, जो रैजोल्यू इन के मूवर है, उन्होंने केवल महेन्द्रगढ तक ही रखा है। यह बात ठीक है कि हरएक पहले अपने घर को देखता है इसलिए उन्होंने इसे केवल महेन्द्रगढ डिस्ट्रीक्ट तक सिमित रखा। ठीक है, उनका दुख भाायद हमारे से भी ज्यादा होगा। मैं यह नहीं कहता कि कम है लेकिन हमारा भी कुछ कम नहीं है। ताहम, हमारा दुःख उनसे भी ज्यादा है। तो भी मैं उनको इस मामले में स्पोर्ट जरूर करूंगा क्योंकि इंसान को सैल्फी ग नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं इनके साथ ही गवर्नमेंट से यह अर्ज करूंगा कि इस फैसिलिटी को हरियाणा के उन सारे एरियाज़ तक ऐक्सटेंड किया जाए जो ड्राट एरियाज़ हैं और जहां पर खारा पानी है, दोनो चीजें होनी चाहिए। ड्राट एरियाज़ तक और जहां पर खारा पानी है, वहां तक हरियाणा सरकार को इस फैसिलिटी को ऐक्सटेंड कर देना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो अब तक प्रोग्राम बना रखा है, मुझे पता नहीं, वह प्रोग्राम इस नजरिये को मददेनजर रखते हुए बनाया है या किसी और बेसिज़ पर बनाया है। अगर उसमें यह नजरिया नहीं रखा गया तो मैं। आपकी मार्फत हरियाणा सरकार से

यह दरखास्त करुंगा कि उनकी जो यह फिफथ फाईव प्लान है, जिस का यह 1974-75 पहला साल है, इसके प्रोग्राम को री-एग्जामिन करके अगर जरूरत समझी जाए तो इन दी लाईट आफ आबजर्वे इन मेड इन दी हाउस, प्रोग्राम मौडीफाई होना चाहिए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं एक बात और भी महसूस करता हूं। मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट इस भाओबे की तरफ ध्यान तो दे रही है लेकिन तेजी कुछ ज्यादा होनी चाहिए। जिन्दगी के लिए मेन आयटम एक यह भी है। बडे आदमियों ने भी यही कहा है। कुटे रान्ज की जरूरत नहीं है। यह तो एक ऐसी चीज है जिसमें कुटे रान्ज की जरूरत नहीं मालूम देती। यह लाईफ के लिए एक बेसिक जरूरत है कि आबपा पि के लिए पानी चाहिए, चाहे वह नहर का हो, चाहे ट्यूबवैल का हो और पीने के लिए मीठा पानी चाहिए। मैं यह जरूर कहूंगा कि जिन एरियाज़ में मीठा पानी है, ट्यूबवैल लगे हुए हैं। वाटर-वर्क्स के लिए प्रायोरिटी उन्ही एरियाज़ को दी जानी जरूरी है जो ड्राट एरियाज़ हैं या जहां पर खारा पानी है।

इसके अलावा अब मैं कुछ बातें अपनी गवर्नमेंट से अपनी कांस्टीच्यूएंसी की बाबत भी अर्ज करना चाहता हूं। अपनी कांस्टीच्यूएंसी के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि आप सर्वे करवा कर देख लें, मेरे ख्याल में करीब-करीब सारी कांस्टीच्यूएंसी में खारा पानी है। किसी गांव में मीठा पानी मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता। मैं अपनी कांस्टीच्यूएंसी में पहले तो दो महीने में हर गांव में टूर पर जाता रहता था लेकिन जब से पेट्रोल के दाम बढे हैं, मेरा टूर रिस्ट्रीक्टीड हो गया है। अब मैं इतनी जल्दी हर गांव कवर नहीं कर पाता, लेकिन मेरी नॉलिज जो है वह ठीक है। पिछले दिनों जून के महीने में मैं एक गांव

भोखपुर गडौली गया। लू चल रही थी। मेरे साथ एक दो साथी और थे। मैंने पूछा सुनाओ भाईयों सब ठीक हैं तो कहने लगे सब ठीक है पर कहने वाली एक बात है। बीच में जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा की मुझे प्यास लगी है। तो एक भाई ने पानी लाकर दिया। पर वे कहने लगे कि आप पानी पी नहीं सकेंगे क्योंकि कुछ तो इसें बदबू का ऐलिमेंट है और कुछ पानी में रेत के कण है। मैं चेयरमैन साहब, बडे दुःख से कहता हूं कि ऐसी रिप्रैजेंटे इन से क्या हासिल है जब हम लोगो को मीठा पानी भी न दे सकें? मेरा दिल भर आया कि मैं एक एम0 एल0 ए0 हूं या क्या हूं जो इनहे पानी भी नहीं मिल सकता। मैंने जब उनसे कहा कि तुम ह्यूमैन बीइंग हो या क्या हो जो ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हो। आज जो यह बात मेरे नोटिस में आई, यह बहुत अच्छा हुआ। चेयरमैन साहब, मैंने यह सोचा कि अगर मैं अपनी सरकार को एप्रोच करुंगा तो इतनी जल्दी काम बनने वाला नहीं हैं। मैं सरकार को ब्लेम नी करता उसके भी कुछ हैंडीकैप्स है। सबसे मेन हैंडीकेप पैसा है। किसी भी काम को करने के लिए फाईनेंस की जरूरत होती हैं। एक वाटर वर्क्स बनाने के लिए कल ही वजीर साहब ने मुझे जवाब दिया। ऐसी जवाब जो जवाब नहीं था। हिन्द से दे दिए और जरब तकसीम मुझ पर छोड दी। मैं यह महसूस करता हूं कि इसके लिए बहुत खर्चा आता है। मैंने उस गांव के लिए क्या स्टैप लियां। मैंने पूछा कोई कच्ची डिग्गी है। कहने लगे है, मैंने कहा मुझे वहां ले चलो। मैंने उनसे यह कहा कि जैसा भी पानी है, मैं जरूर पीऊंगा। अगर मैं पानी नहीं पीता तो वे कहते कि बडा अमीर बनता है। वोट किससे लेगा? फिर मैंने उनसे पूछा कि पंचायत के पास पैसा कितना है? कहने लगे कि 10,000 रुपया है। मैंने कहा कि आप यूं करो कि ईंटे ले आओ।

कहने लगे कि सीमेंट की बिमारी है। मैंने कहा कि सीमेंट की बात आप मेरे उपर छोड़ दो। मैं वहां से सीधा फतेहाबाद आया क्योंकि उस गांव का सब डिविजन फतेहाबाद है। वहां के एस० डी० एम० साहब से कहा कि सीमेंट दे दो। वे बड़े भारीफ आदमी है। कहने लगे कि सीमेंट एक इंस्टालमेंट में तो नहीं दूंगा लेकिन इसकी कमी पूरी कर दूंगा। अब वह डिग्गी नियर कम्पली गन है। मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूं। मैंने नहर के दफ्तर का दरवाजा भी नौक किया। मैं नहर महकमा की भी तारीफ करूंगा क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी हमदर्दी दिखाई। उन्होंने कहा कि आपको जो पानी 12:00 बजे लेना है वह इस डिग्गी के लिए दे दिया जाएगा और इसको आप हमें गं भरा हुआ पाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा छूटकारा मिला है लेकिन यह टैम्पेरी है, इसका जो परमानेंट हल है उसकी तलाश करनी पड़ेगी और मैं यह कहूंगा कि इसके लिए बहुत जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाए। यह तो मैंने एक गांव की कहानी सुनाई। इसके आगे एक गांव है अग्रोहा जहां से कि हिंदुस्तान के अग्रवालो का ओरिजन है। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों जब मैं कलकत्ता गया तो कुछ सेठ साहिबान से मिला क्योंकि इस तरफ के वहां काफी लोग रहते हैं। हमने उनके यहां खाना वगैरह भी खाया। मैं डर रहा था कि कहीं वे सवाल न कर दें और आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि चौधरी साहब अग्रोहा किसकी कांस्टीयूएंसि में पडता है। मैंने कहा कि मेरी कांस्टीयूएंसि में पडता है। उन्होंने कहा कि वहां कोई नि गान होना चाहिए। मैंने कहा कि यह नि गान तो आप लोग ही बनवा सकते हैं। लेकिन वह ऐसा नि गान न हो कि जैसा एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर कामरेड रामकि गन आए और वे किसी के कहने से वहां चले गए और वहां एक बोर्ड लगा दिया इंजिनियरिंग कालेज का।

कुछ दिनों बाद वह बोर्ड उड़ गया। मैं किसी डायरेक्टिव इन से अपनी कांस्टीबल में जाऊँ आई मस्ट गो टू आग्रोहा। इस रोड पर मेरे टायर बहुत घिस गए हैं। क्योंकि मुझे अग्रोहा होकर ही जाना पड़ता है और कोई एंट्री ही नहीं है। मैं यह बात भी कही कि रामकि इन जी जैसा काम नहीं करना चाहिए। जो काम हाथ में लिया जाए उसको पूरा और पक्का करना चाहिए। मैं तो यह भी कहूँगा कि बगैर मेरी नॉलिज के फाईनेंस मिनिस्टर साहब भी वहाँ गए थे और लोगों ने उनसे यह दरखास्त की थी कि इस गाँव में खारा पानी है। अग्रवाल कम्युनिटी क्या कहेगी कि यह हरियाणा सरकार जो इतनी फराखदिल है उस गाँव को मीठा पानी भी नहीं दे सकती। मेरी प्रार्थना है कि उस गाँव को टाप प्रोयोरैटी देनी चाहिए और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने मंत्री महोदय से बात की है और जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनसे गुजारि की है। मेरे ख्याल में उनको खुद ध्यान है। मैंने तो यह अपोरच्युनिटी ली है उनको ध्यान दिलाने की। इस रेजोल्यु इन के लिए मैटीरियल तो बहुत था लेकिन दूसरा भी रेजोल्यु इन है वह भी बहुत जरूरी है और लोगो ने उसके उपर भी बोलना है। इसलिए मैं जल्दी ही वाइंड अप कर दूँगा। चेयरमैन साहब, किसी चीज पर बोलने का फायदा तभी है जब कि सरकार उस पर अमल करने के लिए तैयार हो। हाउस में बोलने का कोई फायदा ही नहीं। कितनी ही रिकवैस्ट कर लें अगर ऐक इन नहीं तो बेकार हैं। चेयरमैन साहब, हरियाणा सरकार के मंत्री जिनके पास यह महकमा है एक और गाँव की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह भी मेरे इलाके में पड़ता है। इसका नाम है किरमारा। यहाँ एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और उस जगह हर महीने हजारों के करीब यात्री आते हैं। वह कहलाता है अग्रोहा परगना और परगना

का मतलब है 20-30 गांव वहां दूर के भी लोग आते हैं, बम्बई के सेठ आते हैं, कलकत्ता के सेठ आते हैं, यू० पी० के सेठ आते हैं और वे लोग यह इम्प्रेन लेकर जाते हैं कि यह मंदिर है जहां पीने का पानी भी नहीं है। मैंने आई० पी० एम० साहब के दफतर में एक नोट भेजा है वैरी रिसेन्टली कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो खुदा के लिए एक लांगिंग टाईप आउटलैट दे दीजिए। इस गांव में पडता है अगरोहा माइनर और नहीं तो कम से कम नहर का पानी पहुंच जाएगा। डिग्गी तो बनवा लेंगे और साल के अंदर कम से कम जो दो मेले होते हैं और उनके अंदर हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं उनको सुविधा मिल जाएगी। चेयरमैन साहब, क्वैचन आवर के अंदर एक सुझाव दिया था कि चीजों को स्पीडली करने के लिए कई चीजें होती हैं जिनकी तरफ अगर तवज्जोह दी जाए तो खर्च भी कम आता है और काम भी जल्दी हो जाता है। जो मौजूदा वाटर वर्क्स हैं उनमें से कुछ तो इतने अच्छे बने हुए हैं कि उन वाटर वर्क्स से और भी गांव फीड हो सकते हैं। जो मौजूदा वाटर वर्क्स हैं उनकी तरफ तवज्जोह दी जाए और उनकी फैसिलीटीज़ ऐडजेसेन्ट विलेजिज़ को मुहैया कर दें। यह एक निहायत जरूरी चीज है। चेयरमैन साहब, आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसके उपर खास तवज्जोह होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, अब मैं दो कपलैट्स कहकर खत्म करूंगा और वे हैं:-

यह माना कि दस्ते सवाली सौ ऐबों का ऐब है,

लेकिन जो सवाली नहीं वह फ़क्त एक दस्ते गैब है।

इस तरफ भी करम रोक के मसीहा करना

कि तुझे आता है बीमार को अच्छा करना।

चौधरी पीर चन्द(बरवाला-एस0 सी0): चेयरमैन साहब, जो रेजोल्यूशन इन सदन के सामने हैं वह निहायत ही जरूरी है और जो चीज जिन्दगी के लिए बहुत जरूरी है उसके लिए यह रेजोल्यूशन आया हुआ है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने गांव-गांव में बिजली पहुंच कर हिन्दुस्तान में नाम रोशन किया है उसी तरह से यह भी निहायत जरूरी चीज है। हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी की बहुत कमी है। हमारे जिले के अंदर भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अब भी खारा पानी है। ऐसे गांव 649 हैं और ये सारे ऐसे हैं जहां किसी जगह भी मीठा पानी नहीं है। मेरे हलके के अंदर करीब 70 गांव ऐसे हैं, जिनमें खारा पानी है। कुछ गांव जैसे बोंववा, हसनगढ़, लतानी, कुवाखेडा, मललोडा, खेदड, थिरोडी, स्पामसुख, समाण और कनणाडी। मेरे हलके बरवाला में वॉटर वर्क्स है और वहां उडाहणी है इनको अगर बरवाल के वाटर वर्क्स के साथ लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा। यहां के लोग उस पानी से गुजारा करते हैं जो थोड़ा बहुत जोहड में डलता है। चेयरमैन साहब, उस जोहड में भी एक महीने में एक बारी ही पानी डलता है। बहुत से ऐसे गांव जो जो दूसरे गांव से पानी लाकर गुजारा करते हैं। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो फंडिंग की कमी के कारण काम बंद किए हुए हैं वह किसी न किसी तरह इनकी तरफ जरूर ध्यान दें। सरकार ने बताया है कि इस स्कीम के लिए उसने 75 करोड़ रुपया रखा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि 75 करोड़ की बजाय वह 1 अरब रुपया रखे तो भी थोड़ा है। चेयरमैन साहब, मैं यह बात सदन में इसलिए कह रहा हूँ कि इस विभाग के जो मंत्री हैं वे भी इसी इलाके के हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वे इस तकलीफ को हर तरह से समझते हैं इसलिए मैं उनसे

पुरजोर रिकवैस्ट करुंगा कि यह मसला बहुत अहम है इसके करने में वे हिचकिचाएं नहीं। इन भाब्दो के साथ मैं मंत्री महोदय से उम्मीद रखूंगा कि वे इस ओर गौर करेंगे।

चौधरी राम प्रसाद(बावल-अनूसूचित जाति): आदरणीय चेयरमैन साहब, यह रैजोल्यूशन जो राव बंसी सिंह जी ने रखा है मैं इसकी पुरजोर ताइद करता हूं। मीठे पानी की जिला महेन्द्रगढ को बहुत जरूरत है। महेन्द्रगढ के ज्यादातर गावों में खारा पानी है, चेयरमैन साहब, मैं अपने डिविजन रेवाडी की बात बताऊं कि उसके आस पास जितने गांव है सब खारे पानी के हैं और बावल क्षेत्र में भी 75 प्रतिशत गावों में खारा पानी है। इस खारे पानी की जगह मीठा पानी देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें भी बनाई है जैसे उहीना स्कीम, प्राणथुरा स्कीम, झाबवा स्कीम और जडथल स्कीमें हैं। हरियाणा सरकार ने ये सारी स्कीमें तो बना ली है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि सरकार कहती है कि उसके पास पैसे की कमी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि जहां के लिए स्कीम बनी हुई है, उसको जल्द से जल्द चालू करें क्योंकि इन स्कीमों से सैंकडो गांवों को फायदा होगा। चेयरमैन साहब, उहीना जो स्कीम है उससे कई गांवों को पानी मिलता है। इसी तरह से राजगढ है वह राजस्थान के साथ लगता है वहां भी पानी अच्छा है अगर उस स्कीमसे वहीं से पानी लिया जाए तो खर्चा कम आएगा और अगर इधर से लेंगे तो खर्चा बहुत आएगा। आजकल आप टयूबवैलो के नए कनेक्शन तो दे ही नहीं रहे हैं और जो पुराने कनेक्शन दे रखे हैं उनसे पानी की कमी पूरी नहीं होती। जैसे हमारा रेवाडी भाहर है वहां पर पानी की कमी रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर वहां भी साहबी नदी के साथ टयूबवैल

लगवा दिए जाएं तो ठीक रहेगा। इसके अलावा कई इलाकों में औरते पानी के लिए झगडा करती हैं लेकिन मैंने मर्दों को पानी के लिए झगडा करते देखा है। मैंने एक इलाका देखा जो राजपूतो का इलाका है वहां पर मई पानी भरते हैं। मैं एक गांव में किसी को मिलने चला गया उस गांव में एक मैनेजर भी थे मैंने कहा उनसे भी मिल लूं। मैं उनके घर गया तो मुझे बताया गया कि वे पानी लेने के लिए गए हुए हैं। मैंने वहां से चार फरलांग पर जाकर देखा कि एक घडा तो उस मैनेजर के सिर पर था और एक एक बगलो में था। मैंने उससे कहा कि तुम बैंक में तो बात नहीं करते ? तो कहने लगा क्या करें पानी जो पीना है। तो चेयरमैन साहब, यह है पानी की हालत। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वे महेन्द्रगढ जिले में मीठा पानी दें। हमारे मंत्री महोदय के पास दो किस्म के पानी है। एक पीने का पानी और दूसरा गहर का पानी। अगर वे हमें नहर का पानी भी देदे तो जो कल्लर का पानी है वह मीठा हो जाएगा और जोहडो में भी पानी आ जाएगा। इसके अलावा मेरे इलाके में तीन-चार गांव ऐसे हैं जिनमें पानी डेढ सौ फुट से भी नीचे है। जब कुए से पानी भरने जाते हैं तो दो-तीन रस्सीयां जोडनी पडती है। तब कहीं जाकर एक दो घडे पानी के मिलते हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, सबको इसके बारे में पता है। चेयरमैन साहब, ज्यादा कुछ न कह कर यही कहूंगा कि महेन्द्रगढ जिले में खास कर बावल में पानी की कमी को दूर किया जाए। वहां पर आप देखें कि चारो तरफ राजस्थान है। रेवाडी के पास साहबी नदी में जब बाढ आती है तो वह बहुत ज्यादा नुकसान करती है। एक चीज और देखिए कि उस इलाके में गेहूं नहीं होता। वहां पर सरसों के सिवाए कुछ नहीं होता क्योंकि

वहां का पानी ऐसा है अगर उस पानी को गेहूं या कोई अन्य बीज कर दें तो सारी फसल मर जाती है। तो मैं ज्यादा कछ न कह कर इतना ही कहूंगा कि इस इलाके की तरफ ध्यान दिया जाए और दोनो तीनो स्कीमें जो अधूरी पडी हैं, इन से 100 पचास गावों को पानी मिल सकता है और मैं यह भी कहूंगा कि डहीजा की स्कीमी को बडा कर दिया जाए, उस से भी पानी मिल जाएगा। एक पास के गांव में जहां पानी मिला है वहां कर्नल महा सिंह जी भी गए थे और वह ऐलार कर आए कि पियोपर, रामपुरा, इन सब को पानी मिल जाएगा लेकिन आज तक वहां पानी नहीं मिला, कभी पाईप नहीं होते और कभी पैसों की कमी पड जाती है, लेकिन जहां पानी मिलता है वहां की भी हालत ऐसी है कि कभी ट्यूबवैल नहीं चलता और कभी बिजली नहीं होती। तो यह एक दूसरी प्राब्लम है। इस के अलावा इन्होने पानी के कैंक इन तो दे दिए लेकिन एक एक गांव में एक नल लगाया हैं। वहां पर रोज झगडे होते है। कर्नल महा सिंह जी पांच 6 गावों में खुद जाकर उद्घाटन करके आए थे। चेयरमैन साहब, एक कुनैव इन के क्या मायने हैं। वहां पर पचास पचास औरते बर्तन लेकर बैठ जाती है। जब नल आता है तो दो चार घडे भर जाते है और फिर पानी बंद हो जाता है। इसके अलावा हरिजनो के मोहल्ले में कोई नल नहीं है। मैं यह निवेदन करुंगा कि कम से कम तीन नल हरएक गांव में जरुर लगाने चाहिए, एक हरिजनो के लिए, एक स्कूल के लिए और एक गांव के लिए, बस मैं ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ यही अपील करुंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर पानी के मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए।

राव दलीप सिंह(कनीना): चेयरमैन साहब, इस रेजोल्यू इन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और सब मैम्बरान साहिबान ने

अपने-अपने ख्यालात का इजहार किया हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ हरियाणा में सबसे पिछडा हुआ इलाका है और वहां पर पीने के पानी की बडी तकलीफ है, लोगों को काफी दूर दूर से पानी लाना पडता है, गर्मियों के दिनो में पानी जोहडो में भी नही मिलता और जहां कही कुएं है वह भी खु क हो जाते है और इस वक्त वहां पर वाटर लैवल कोई सौ फूट से नीचे जा चूका है। जब हमारे वहां कोई इधर का मेहमान आ जाता है और मीठे पानी का सवाल आता है तो वह सचमुच मीठा समझ कर यह जवाब देता है कि नही मैं तो सादा पानी ही पिउंगा तो फिर लोगों को बताना पडता है कि सादे पानी को ही मीठा कहते है। चेयरमैन साहब, आज आजादी के इतने सालो बाद भी लोग पीने के पानी दो दो मील से गर्मी में लाते है। तो यह हमारे लिए बहुत भार्म की बात है कि आज जो हुकमरान है वह एयरकंडी ांड मकानों में रह सकते है, उन की कोठीयों में गर्म पानी और ठंडे पानी का इंतजाम हो सकता है, उन के पास कारें है और आराम के लिए सोफे और कुर्सियां है लेकिन जब तक लोगों को पीने तक को पानी न मिले तब तक यह उनके लिए कोई भान की बात नही है। आज आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम उनको पीने का पानी नही दे सके तो हमारा सर भार्म से झुकना चाहिए। एक तरफ तो लोग दो-दो तीन-तीन मील से गर्मी में पानी लेकर आते है और हम एयरकंडी ान मकानों में रहते हैं यह क्रेडिट की बात नही। अभी यहां पर एक भाई साहब गुलाब सिंह ने सुझाव दिया था कि पीने का पानी का इंतजाम करने के लिए वाटर सेंस लगा दिया जाए। मैं कहता हूं कि लगा दिया जाए लेकिन मुझे फिर भी भाक है कि हमें फिर भी पानी नही मिलेगा। उस रुपये को भी और और जगहो के लिए खर्च कर

लिया जाएगा। हमें चेयरमैन साहब, अंग्रेजों के जमाने में पानी नहीं मिला, ज्वायंट पंजाब के वक्त पानी नहीं मिला और अब अब अगर हरियाणा बनने के बाद भी पानी न मिला तो कब मिलेगा। हमारी सरकार को फोरी तौर पर पहले ऐसे इलाके में पानी देने का प्रबंध करना चाहिए जहां पर पिटीएबल कन्डीशन है। चौधरी मेहर चंद जी ने कहा था, उन लोगों को कुर्बानी वाकई में करनी चाहिए, जहां नहरें हैं, जहां पिटीएबल कन्डीशन है वहां पानी देना चाहिए, वहां ऐसी हालत है कि गर्मी में कोई आदमी रह नहीं सकता। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था।

सिंचाई और विद्युत मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): सभापति महोदय एक प्रस्ताव राव दलप सिंह और राव बंसी सिंह का सदन के सामने प्रस्तुत है और काफी देर से उस पर चर्चा चल रही है। मेरे साथियों ने जो विचार, जो भावनाएं तथा जो उद्गार इस सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं मैं उन से सहमत हूँ। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या हरियाणा प्रदेश में है और यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि जहां पीने का पानी भी बलबल न हो इससे बड़ी और कोई तकलीफ किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं आप के सामने ऐसे तथ्य भी रखूंगा जिनसे यह प्रमाणित होता है कि हरियाणा बनने के बाद कितना ध्यान इस समस्या को हल करने के लिए दिया गया। संयुक्त पंजाब में सन् 1954 के अंदर इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि ग्रामों के अंदर पीने का पानी की सुविधा दी जाए और सन् 1955 में इस पर काम शुरू हुआ। 1955 से 1966 तक जब हरियाणा अलग वजूद में आया तो केवल 170 गावों को पीने का पानी दिया गया था जिस पर 2 करोड़ 20 लाख रुपया सरकार

का खर्च हुआ था। उस के पश्चात हरियाणा बनने से सन् 1968 तक 33 गांवों को और पानी देने की सुविधा प्रदान की गई। फिर चौधरी बंसी लाल जी की मौजूदा सरकार आने के बाद इस समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। यह कोई जबानी बात नहीं है इसको प्रमाणित करने के लिए मैं आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सन 1968 से 31 मार्च, 1969 तक 54 गांवों को पानी दिया गया, फिर 1969-70 में 84 गांवों को पानी दिया गया, 1970-71 में 63 गांवों को और 1971-72 में 125 गांवों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई। फिर 1972-73 में 66 गांवों को और पानी दिया गया। इस प्रकार अब तक हरियाणा के अंदर टोटल 714 गांवों को पीने का पानी की सुविधा दी जा चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कुल गांवों की संख्या 6731 है उन में से 4180 गांव ऐसे हैं जिन में पीने के पानी की समस्या है, या खारा पानी है, या कुओं में कम पानी है या कहीं बिल्कुल पानी नहीं है। हरियाणा के अन्दर मैंने वे गांव भी देखे हैं, जो कि मेरे इलाके में मौजूद हैं, जहां पर किसी प्रकार का पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, वे लोग छोटे-छोटे कुण्ड बनाते थे और उस के अंदर बारिश की एक एक बुंद का पानी इकट्ठा करते थे और उस को ताला लगा कर बंद करके रखते थे जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को तिजौरी में रख कर ताला लगा कर, सम्भाल कर रखता है और जब भी जरूरत पडती है तो उस में से एक एक गडवी पानी की निकाल करके निर्वाह करते थे। वहां यह हालत थी कि जब कोई मेहमान जाता था तो उसको पीने के लिए दूध तो मिल जाता था लेकिन पानी नहीं मिलता था। उपाध्यक्षा महोदया आज उन लोगों को पचास पचास मील लम्बी पाईप बिछा कर पानी पहुंचाया गया है। इस

प्रकार का इंतजाम चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आने के बाद किया गया है। कुल 4180 गावों में पीने का पानी की समस्या थी जिन में से 714 गावों को यह सुविधा दी जा चुकी है और उस के बाद 3466 गांव अब भी ऐसे है जिन को पीने के पानी की सुविधा देनी बाकी रहती है। इस के लिए हमने अनुमान लगाया है कि साढ़े 76 करोड़ रुपया इन सब गावों को पानी देने के लिए चाहिए। इतना फण्ड हमें मिले तो इन सब गावों को पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है। आज कल जो मैटिरियल की कीमते है उनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है।

चौधरी चांद राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रस्ताव तो सिर्फ महेन्द्रगढ जिले के बारे में ही है।

उपाध्यक्षा: चौधरी चांद राम जी आप इसे दोबारा पढ़िए।

श्री बनारसी दास गुप्त: उपाध्यक्षा महोदया, अगर मैंबर साहिबान सारी स्टेट के बारे में हालात जानना चाहते है तो वह बता देता हूं लेकिन अगर खाली महेन्द्रगढ के बारे में ही जानना चाहते है तो वह बता देता हूं। मेरे पास सारे ही आंकडे मौजूद है।

उपाध्यक्षा: यह प्रस्ताव पीने के पानी के बारे में आया है और सारे मैम्बर सहिबान ने अपने अपने हलका के बारे में तकलीफात बताई है और यह मसला भी सारी ही स्टेट का है इसलिए यह ज्यादा ठीक होगा अगर उसे सारे हरियाणा के बारे में ही बताया जाए।

चौधरी चांद राम: मेरी सबमि तन यही थी कि चौधरी बंसी लाल जी के आने के बाद कितने गावं को पानी दिया गया वह बताया जाए और फिर जिलावार भी बताया जाये कि किन जिलों में कितने कितने गावं को उनके आने के बाद पानी दिया गया है।

श्री बनारसी दास गुप्त: मुझे इस बात पर कोई आपत्ती नहीं है और अगर वह चाहते हैं कि महेन्द्रगढ जिला के बारे में ही बताऊ तो वह फिगरज भी मेरे पास मौजूद है। सारी बात बता देता हूं। लेकिन मैं सारी स्टेट के बारे में स्थिती इसलिए बता रहा था क्योंकि जो सम्मानित सदस्य यहां बोले हैं उन में से बहुतो ने अपने अपने हलका के बारे में दिक्कत बताई है। और यह कठिनाई भी सब जगह कम या ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं सारी पिक्चर पे टा कर रहा हूं, लेकिन चांद राम जी को ऐतराज हो तो मैं केवल महेन्द्रगढ की ही बात कर देता हूं।

चौधरी चांद राम: मुझे कोई नहीं जो बात थी वो मैंने बता दी।

श्री बनारसी दास गुप्त: अगर जिलावार फिगरज पूछना चाहते हैं कि किस जिला में कितने गावं को पीने का पानी दिया गया उस स्थिती इस प्रकार है।

अम्बाला 136 गांव

भिवानी 230 गावं

महेन्द्रगढ 93 गांव

रोहतक 44 गांव

सोनीपत 6 गांव

कुरुक्षेत्र 10 गांव

जींद 28 गांव

हिसार 90 गांव

करनाल 3 गांव

इस प्रकार 713 गांव के यह फिगरज मेरे पास मौजूद है—(विघ्न)— करनाल में क्योंकि अण्डर ग्राउंड पानी मीठा है इसलिए वहां पर थोड़े गांव को पानी दिया गया—

चौधरी चांद राम: कुल कितने गांव में पीने के पानी की समस्या है वह भी जिलावार बता दें।

श्री बनारसी दास गुप्त: जिन गांव में पीने के पानी की समस्या है वह इस प्रकार है

अम्बाला 554 गांव

भिवानी 464 गांव

महेन्द्रगढ 623 गांव

रोहतक 431 गांव

सोनीपत 246 गांव

कुरुक्षेत्र 41 गांव

जींद 275 गांव

हिसार 689 गांव

करनाल 45 गांव

चौधरी चांद राम: अब एक और बात बता दें कि जिला महेन्द्रगढ और कुछ दूसरे जिलो में ज्यादा गांव में पीने के पानी की समस्या है लेकिन वहां थोड़े गांव को पीने का पानी क्या मुहैया किया गया और भिवानी में ज्यादा गांव को क्यों दिया गया इसका कारण क्या है?

श्री बनारसी दास गुप्त: उपाध्क्ष महोदया, असल में बात यह है कि चौधरी चांद राम जी को ज्यादा चिढ भिवानी से है। वैसे वह बड़े बड़े जलसे भी भिवानी में ही करते हैं और—

चौधरी चांद राम: मुझे भिवानी से कोई चिढ नहीं मैं तो बराबरी की बात कर रहा हूं कि इधर ज्यादा और उधर कम क्यों?

श्री बनारसी दास गुप्त: उपाध्क्ष महोदया, इनकी भिवानी चिढ का एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां से इनको चंदा कम मिला हो— यह गिला तो इनको हो सकता है लेकिन जहां तक पीने के पानी देने की बात है भिवानी में यह तकलीफ ज्यादा थी इसलिए उस और ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसी तरह से महेन्द्रगढ में भी ज्यादा ध्यान दिया गया है और आगे जब मैं महेन्द्रगढ और दूसरे जिलो के बारे में विस्तार से बात रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि सब जिलो की तरफ

पूरा ध्यान दिया जा रहा है और सिर्फ एक जिले की तरफ ही नहीं दिया जा रहा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हरियाणा के अंदर 3466 गांव ऐसे अब भी हैं जिन में पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। इन सब गावों को पानी की सुविधा देने के लिए हमें साढ़े 76 करोड़ रुपया चाहिए लेकिन आप जानते हैं कि फंडिंग की बहुत कमी है हमारी जो यह पहली अप्रैल से पंचवर्षीय योजना चल रही है इस में हमें केवल 29 करोड़ रु ग्रामीण क्षेत्र में वाटर सप्लाई योजनाओं के लिए मिले हैं और इस पैसे से हम 1200 से 1400 गांव तक ही यह सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाने के बाद 2066 गांव ऐसे बच जाते हैं जिन में यह पीने के पानी की तकलीफ मौजूद रहेगी। अब मैं कह नहीं सकता कि छठे प्लान में कितना हमें धन मिलेगा और फिर उससे अगली योजना में कितना मिलेगा। यह जो धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है कितनी जल्दी हम इस काम को पूरा कर सकते हैं इसके बावजूद भी उपाध्यक्षा महोदया मुझे इस बात का खेद है कि कुछ पैसे की कमी होने के कारण इस योजना में हमें 29 करोड़ रु दिए भी गए हैं उन में से इस योजना के इस पहले साल में हमें रुरल वाटर सप्लाई के लिए केवल 144 लाख रुपये दिए गये हैं। अगर हिसाब से देखा जाए तो कम से कम पहले साल के पांच करोड़ रुपया मिलना चाहिए था लेकिन जो प्लानिंग और प्लानिंग बोर्ड है और जो इसका वर्किंग ग्रुप है उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने और सारे साधन देखने के बाद 144 लाख रुपया ही इस साल के लिए दिया है। इसमें हम इस साल 100 गावों को और पीने के पानी की सुविधा दे सकते हैं। यह हालत और नक्का है जो मैं सदन के सामने पेना करना चाहता था। महेन्द्रगढ़ के बारे में जिसके लिए यह प्रस्ताव आया है, उसकी स्थिती

इस प्रकार है। जिला महेन्द्रगढ में कुल 683 गांव है और उन में से 623 गांव ऐसे है जिन में पीने के पानी की तकलीफ है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि जिला महेन्द्रगढ की समस्या बहुत ही गंभीर है इस में कोई सन्देह नहीं। इन 623 गावों में से 93गावों को अब तक पीने के पानी की सुविधा दी गई है। और बाकी 76 गावों के योजना अंडरप्रोग्रैस है। 31 और गांव की योजना बन कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवैल ली जा चुकी है। और 76 गांव ऐसे है जिन के बारे में स्कीम बना कर डिवलैप्मेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दी गई है। 145 गांव के लिए योजना बनाई जा रही है और इसके बाद 263 गांव बच जाते है अभी 7 जुलाई 1974 को सैनेट्री बोर्ड की मिटिंग हुई थी उसमें जो 144 लाख रुपया मिला है उस में से 11लाख 81 हजार रुपया हम ने जिला महेन्द्रगढ को दिया है उन स्कीमो को पूरा करने के लिएजो चल रही है। हमें 4 करोड 16 लाख 87 हजार रुपया और चाहिए केवल जिला महेन्द्रगढ की इस समस्या को दूर करने के लिए। मैने जिला महेन्द्रगढ और सारे स्टेट की स्थिती आपके सामने पे । की। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या की ओर सरकार का पूरा ध्यान है। जहां तक हमारे पास साधन जुटते है और जहां तक हम और साधन जुटा सकते है, इस समस्या को हल करने की ओर हम पूरा ध्यान देंगे। जो पिछडे हुए इलाके और कहरजदा इलाके हैं उन के लिए हमने एक रियायत दी हुई है कि रुरल वाटर स्कीम के तहत जो 12 फिसदी बैनिफि गायरी भोयर देना पडता है, वह उनका माफ किया हुआ है। जो अकाल पिडित इलाके हैं जैसे भिवानी, रोहतक, झज्जर की तहसील, अम्बाला की नारायणगढ तहसील का इलाका, इन को हमने बैनिफि गायरी भोयर से

एग्जम्पट किया हुआ है, उन से 12 फिसदी भोयर नही लेते। इस प्रकार उपाध्यक्षा महोदया जो पिछडे हुए इलाके हैं उन पर किसी प्रकार का बोझ डाले बिना उन तक पीने का पानी पहुंचाएं। मै सरकार की ओर से वि वास दिलाता हूं कि महेन्द्रगढ, भिवानी, झज्जर का इलाका, और अम्बाले जिले में नारायणगढ का इलाका जो पिछडा हुआ है, इनको इस काम के लिए सुविधा प्रदान करने में टाप प्रोयैरिटी देंगे। मै इस आ वासन के साथ सारी तस्वीर हाउस में रखने के बाद जो प्रस्तावक महोदय है, उनसे प्रार्थना करुंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें क्योंकि सरकार को इस तरफ पूरा ध्यान है, पूरे चेश्टा और भाक्ति के साथ इ मसले को हल करने के लिए लगे है। मै पुनः अपने सम्मानित सदस्यों से अपील करुंगा कि इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया जाए।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

राव बसी सिंह (अठेली): स्पीकर साहब, मंत्री महोदय के आ वासन पर मैं अपना रैजोल्यू इन वापिस लेता हूं।

Mr. Speaker: Is it a pleasure of the House that the resolution be withdrawn

Voices: Yes

Mr. Speaker: The resolution is by leave withdrawn.

The resolution. was, by leave of the House, *withdrawn*.

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण—चौधरी चांद राम द्वारा

चौधरी चांद राम: आन ए पर्सनल एक्सप्लेने इन सर। श्री बनारसी दास जी ने यह कह दिया कि मुझे भिवानी से तकलीफ है कि

इन्होंने वहां के गावों में पानी क्यों दे दिया। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा था कि भिवानी में 713 गावों में 630 गावों में पानी दिया। महेन्द्रगढ़ के 741 गावों में से 93 गावों को दिया और रोहतक के 430 गावों में से 44 गावों को दिया। तो मैंने यह कहा था कि सब जिलों को हिसाब से पानी दिया जाए।

श्री बनारसी दास गुप्त: जिला महेन्द्रगढ़ में टोटल 683 गाव हैं और 623 गावों में यह समस्या है। टोटल 700 गांव नहीं हैं, 683 हैं। अब तक अब तक इन में से 100 के करीब गावों को पानी दे दिया है और बाकी के लिए स्कीम चल रही है।

गैर-सरकारी संकल्प-

हरियाणा राज्य में परमाणु केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन करने के सम्बन्ध में।

Ch. Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir, I beg to move- That this House recommends to the State Government to approach the Central Government for the installation of an Atomic Station in the State of Haryana.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House recommends to the State Government to approach the Central Government for the installation of an Atomic Station in the State of Haryana.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, टाईम थोड़ा रह गया है, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, आप हाउस का टाईम ओर एक्सटेंड कर दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

बैठक के समय में वृद्धि

Mr. Speaker: The time of the House is extended by half an hour.

गैर सरकारी संकल्प

हरियाणा राज्य में परमाणु केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन करने के सम्बन्ध में (पुनराम्भ)।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, भारत सरकार ने अणु विस्फोट करके दे आ की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। इससे पहले सरकार कहा करती थी कि हम अटॉमिक रिसर्च नहीं करेंगे लेकिन अब इस पर रिसर्च की गई। अब अगर सरकार अटॉमिक वैपन भी बनाये तो हम उसका भी बहुत जोरदार स्वागत करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, इस सरकार के सामने मैंने जो रैजोल्यूशन प्रस्तुत किया है, उसके प्रस्तुत करने का कारण यह है कि हरियाणा प्रान्त कृषि प्रधान प्रान्त है। यह प्रांत जरायत के उपर निर्भर करता है और 82 फिसदी पापुले आन सरकारी आंकडो के अनुसार एग्रीकल्चर पर इनहसार करती है। हरियाणा की इकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट, 1971-72 के अनुसार मैक्सिमम पापुले आन एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। इसमें लिखा है—

“Haryana is predominantly an agriculture State. 82% of its population derived livelihood from agriculture.”

स्पीकर साहब, इस स्कीम की पोजी आन हो, कि प्रान्त इनहसार ही खेती के ऊपर करता हो और उस के अंदर कुल रिपोर्टिंग

एरिया है हरियाणा का वह 44.2 प्रसैंट हैक्टेयर हो और इस रिपोर्टिंग एरिए में ऐसा एरिया भी शामिल होगा जो इसके अंदर आये। लेकिन इकोनोमिक सर्वे के अनुसार इरीगे टन के नीचे जो 1972-73 की इकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट मेरे पास है उस में लिखा है—

“Irrigation facilities in Haryana are quite wide spread. The total irrigated area in the State in 1971-72 was 23.25 lakh hectares. It accounted for 46% of the gross areas sown.”

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 46 प्रसैंट एरिया हरियाणा में इरीगेट हुआ है और 54 प्रसैंट एरिया ऐसा है जिसको हम पानी की कमी की वजह से, बिजली की कमी के कारण इरीगेट नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार को पता चल कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया इरीगेट हो। नहरें बनाई जा रही हैं, मैंने नहरों के बारे में सवाल किया था तो उसके जवाब में बताया गया था कि कुछ नहरों के अन्दर सेलाब का पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी को युटिलाईज करने के लिए इन्तजाम किया ताकि इन नहरों के द्वारा पानी खेतों तक पहुंचा सके। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसिस ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिनको हम अवाईड नहीं कर सकते। जैसा की बारिश का न होना। यह हमारी नहरों के सामने है कि बारिश पिछले साल भी नहीं हो पाई और इस साल भी बारिश नहीं हो रही है। तो इस हालत में नहरों में पानी का सेलाब कैसे आएगा। इसलिए सेलाब से जो पानी मुयस्सर होता है वह भी नहीं होगा। हरियाणा और पंजाब का जहां तक ताल्लुक है, स्पीकर साहब, ये दोनों प्रान्त ऐसे हैं जो सारे देश का अन्न संकट दूर कर सकते हैं। अगर इन दोनों प्रांतों के पूरे साधन उपलब्ध करवाएं जाएं, बिजली इनको पूरी मिले, पानी पूरा मिले तो यह

दोनो प्रान्त खडे होकर आज जो करोडो रुपए का अन्न कनाडा और दूसरे दे गो से मंगवाया जाता है, उसको बंद करवाने में मदद कर सकते है। अगर, स्पीकर साहब, बाहक के दे गो से अन्न मंगवाना बन्द करना है, दे गो को आत्मनिर्भर बनाना है तो हरियाणा और पंजाब को बिजली और पानी के साधन भारत सरकार को देने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया इरीगेट हो सके। अगर सरकार सचमुच चाहती है कि दे गो में अन्न संकट खत्म हो तो सबसे पहली आव यकता जो है, वह बिजली की है क्योंकि बिजली के द्वारा ही ट्यूबवैल चलेंगे, अन्य कई प्रोजैक्टस चलेंगे। जहां तक कटाई और दूसरी चीजो का सम्बन्ध है, उसके लिए भी आज मीने बन रही है। तो सारी कृशि का इनहसार एक बिजली के ऊपर खडा हुआ है लेकिन बिजली की द गो जो है, वह सोचनीय है। आज हमारे सामने एक बडे संकट की द गो बिजली है। उसका भी एक कारण है क्योंकि जहां तक बिजली के उत्पादनका संबंध है, उसके उत्पादन के हरियाणा के अंदर कई साधन नही है। बिजली हमें भाखडा से मिलती है, डेसू से मिलती है। हमें स्पीकर साहब, एक किताब परसों दी गयी जिसका नाम है: ऐनुअल फानैि यल स्टेटमेंट-बजट-ऐस्टीमेट्स 1973-74। इसके पेज 22 पर, स्पीकर साहब, पावर पोजी ान का, पावर प्रोजैक्टस का विवरण लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि-

“Power Position and Power Projects”

The main source of supply of power in the Haryana State are Bhakra Nangal Project. I.P. Thermal project and small Thermal Genration sets at Faridabadn and Surajpur. Due to fall in the water level of the Bhakra rsorvior the power position from Bhakra Complex continues to be very tight. Against maximum demand of

669 MW during the year 1973-74, the total available generation capacity from all existing schemes including purchases would be 352 MW, thus there will be shortfall of 317 MW and this will go up further rapidly in the subsequent years.

तो ऐग्जिस्टिंग जेनरेटिंग कैपेसटी जो है वह कहां से है इसके बारे में लिखा है—

“A list of the generation projects at present in operation and the projects taken/proposed to be taken in hand is given below-

Sr No.	Name of the Project	Installed Capacity
1.	Share of Haryana State in the power Generation in the Bhakra Nanga Project as tentatively fixed at 39.5 per cent.	76MW
2.	Indraprastha Thermal Station Delhi/3 rd Share of the total	62.5 MW
3.	Thermal Set at Faridabad	15 MW
4.	Thermal Set at Surajpur	6.8 MW
5.	Diesel Sets at Ambala and Faridabad	3 MW

तो, स्पीकर साहब, हमारे हरियाणा के अन्दर बिजली के उत्पादन के अपने कोई साधन नहीं हैं। हैं तो बड़े मामूली है। बिजली जितनी मिलती है वह बाहर से मिलती है। तो ऐसी स्थिति के अन्दर आज हम देखते हैं कि खेतीबाड़ी के लिए रोज ही इस प्रकार की पुकार रहती है कि बिजली न होने के कारण पानी जो है, वह खेतों को पूरा

नहीं मिलेगा। अभी धान की फसल होने वाली है, उसके लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा के अन्दर देने का इन्तजाम हमारी सरकार के पास नहीं है। आज ऐसी अवस्था हो रही है कि भाखडा में पानी का जो लैवल है, वह इतनी नीचे चला गया है कि भायद अगले दो महीनो के अन्दर हमें जितनी बिजली मिल रही है वह भी न मिले। तो आज एक संकट की स्थिती हमारे सामने है और इस स्थिती के अन्दर सुधार आने की कोई बात नजर नहीं आती। आखिर भाखडा का प्रोजैक्ट जितना काम करता है, उतना ही तो करेगा। भाखडा से जितना हिस्सा हमें मिलना चाहिए उतना ही तो मिलेगा। ठीक है फरिदाबाद और पानीपत में बिजली बढ़ाने की बात हो रही है लेकिन प्लांटस लगने में कितना टाईम लगेगा, कितना रुपया लगेगा और उससे कितना फायदा हम हासिल कर पाएंगे, यह भी एक समस्या की बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि यह हरियाणा प्रान्त विकास की ओर तेजी से दौड़े तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। खेतीबाडी में देा के अन्दर अन्न संकट खत्म करवाने में हरियाणा रीठ की हडडी के तौर पर काम करता है। लेकिन इसके पास अपने रिसोर्सिज बहुत कम है। अगर सरकार के पास रिवैन्यू नहीं आएगा तो सरकार चाहे जितनी भी खुानुमा तस्वीर सदन के अन्दर या बाहर रखने की कोशिश करे, यह सच्चाई को छुपा नहीं सकती। प्रान्तोत्तर काल के अन्दर हम जब भी इनसे कोई सा प्रान्त न पूछें तो यही कहा जाता है कि फंड्ज की कमी के कारण हम इस काम को और आगे नहीं बढ़ा पाये। मैं यह बात आोचना की नीयत से नहीं कर रहा, बल्कि वास्तविकता बता रहा हूँ कि हरियाणा के पास रिसोर्सिज कम हैं। अब रिसोर्सिज कैसे बढ़ सकते हैं। जहां तक खेती बाडी बढ़ाने का ताल्लुक है वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देा का बहुत सा अन्न

बाहर से मंगवाना पडता है और उसमें हमारा बहुत सा फारेन ऐक्सचेंज चला जाता है। यदि दे 1 के प्रत्येक नागरिक को जो कि इस दे 1 करोडो की संख्या में है, अन्न प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए चाहे कोई भी प्रान्त काम करता है, उसको भारतीय सरकार को उपयुक्त साधन मुहैया करने पडेंगे। इसमें कोई भाक नही कि इससे उस प्रान्त को भी फायदा होता है जिसको इस तरह के साधन उपलब्ध कराये जाते है लेकिन यह बात भी दरुस्त है कि इससे दे 1 का भी भारी फायदा होगा। रिसोर्सिज बढाने के लिए प्रांत की सरकार को भी विचार करना होगा और वे रिसोर्सिज तभी बढेगे अगर हरियाणा इंडस्ट्रीज की ओर ज्यादा ध्यान देगा। तो स्पीकर साहब, इस तरीकेसे मैने यह रेजोल्यूशन मूव किया है क्योंकि हरियाणा सरकार में यह कहा जाता है और ट्रेजरी बेंचीज से मैम्बर साहिबान भी कहा करते है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब का सैन्ट्रल गवर्नमेंट मे बडा रसूख है, बडा होल्ड है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करुंगा कि इस होल्ड का और रसूख का फायदा उठाने की कोर् 1 1 करें और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से कहा जाये कि हरियाणा के अन्दर एक एटोमैटिक स्टे 1न लगाया जाए। अगर उन्होने ऐसा कर दिया तो हरियाणा का एक एक व्यक्ति इस चीफ मिनिस्टर को याद रखेगा।

मुख्य मंत्री(चौधरी बंसी लाल): अब क्या आप भूलते है, मुझे तो आप अब भी याद रखते है (हंसी)

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): वह तो आप दूसरी तरह से याद करवा लेते है। यह तो आपके स्वभाव में है। तो स्पीकर साहब,

मेरा इस रैजोल्यूशन का जो भाव है वह यह है कि हरियाणा का विकास, हरियाणा की तरक्की, हरियाणा की बहबूदी बिजली के द्वारा हो सकती है। हम चाहे कितनी ही बिजली भाखडा से लेकर, डेसू से लेकर, थर्मल प्लांट लगा कर इस कमी को पूरा कर ले लेकिन पूर्ण रूप से पचास साल गुजरने के बाद भी हम आर्थिक विकास नहीं कर पायेंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है। अगर हम चाहते हैं कि हरियाणा पूरी तरक्की करे तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर पूरा दबाव डालें कि वह हरियाणा के अन्दर एक एटोमिक स्टेशन लगाए। मैं यह भी कहूंगा कि हमारी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहां गुजरात के अन्दर, महाराष्ट्र के अन्दर और वेस्ट बंगाल के अन्दर और दूसरी स्टेट्स के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रही है लेकिन हरियाणा को आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति बड़ी भेदभावपूर्ण है। उसे यह नीति नहीं बरतनी चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हरियाणा की ओर से मांग करता हूँ हमारे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, हरियाणा को विकास की ओर ले जाने के लिए यह एटोमिक स्टेशन लगाया जाये ताकि हरियाणा 55 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे सके। यहां पर एटोमिक स्टेशन लग जाने से पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को बिजली मुहैया हो सकती है। इन भावों के साथ मैं आपका मकसूर हूँ कि आपने मुझे समय दिया और एक बार फिर सरकार से कहूंगा कि वह अपना पूरा रसूख इस्तेमाल करके यहां एटोमिक स्टेशन लगवाने की प्रबन्ध करें।

श्री गौरी भांकर (नरवाना): स्पीकर साहब, आज यह हाउस में बिजली के बारे में रैजोल्यूशन आया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जहां पर नहरों

पर छोटे छोटे पचास पचास या सौ सौ फुट के वाटर फॉल है वहां पर जनरेटर लगायें जाएं उनसे बिजली भी तैयार हो सकती है ओर उसमें लागत भी कम आएगी।

मैं दुबारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर सर्वे करा के छोटे छोटे बिजली के स्टे इन लगायें जाए ताकि लोगो को बिजली मिल सके।

चौधरी चांद राम (बबैन अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें दो रायें हो ही नहीं सकती कि यह सारा सदन हरियाणा सरकार से यह सिफारिश करें, यह प्रार्थना करे कि हमारे इस रीजन में, इस स्टेट में परमाणु केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार को राजी करें। यहां पर अभी अभी बताया गया है कि एटोमिक स्टेशन की क्यों जरूरत है? इसके बारे में तो कोई दलील देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अणु भाक्ति जो है इस भाक्ति का मुकाबला बिजली या कोई दूसरी भाक्ति कर ही नहीं सकती। यह एक ऐसी भाक्ति है जिसके जरियें हमारी कई प्रकार की विकास योजनाएं चालू हो सकती है। एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं। पिछले 7-8 साल से, और उससे पहले जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था यानि जब पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन हुआ उसके बाद भी न हरियाणा में और न पंजाब में ऐसी कोई योजना आई है। इस आधार पर हम यही कह सकते है कि हमारे इस रीजन के साथ सौतेली मां जैसा सलुक हो रहा है। हमारा रीजन ऐसी है कि जहां पर ज्यादा पैदावार हो सकती है, जहां पर क्षमता ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है, वहां पर उसको ऐक्सप्लायड नहीं किया जाता। हम महंगाई को

रोक ही नहीं सकते जब तक कि मुल्क में पैदावार ज्यादा नहीं होती। मुल्क में पैदावार ज्यादा केवल एक ही तरीके से हो सकती है और वह है जहां पर क्षमता ज्यादा है वहां पर उसे ऐक्सप्लायट किया जाए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि से ही सारी चीजे उत्पन्न होती है। जो इंडस्ट्रीज है, वे भी खेती की चीजों पर निर्भर करती है खेती से सिर्फ अन्न ही पैदा नहीं होता बल्कि जो दस्तकरियां हैं, उनका रा-मैटीरियल यानी कच्चा माल भी पैदा होता है। कच्चा माल ज्यादा पैदा करने के लिए और अन्न ज्यादा पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि इन्टैन्सिव कल्टीवेटिंग की जाये और उसके लिए ट्यूबवैल्स को पूरी भाक्ति दी जाए या किसी दूसरे तरीके से उद्योगों को अटॉमिक भाक्ति से चलाया जाए। ऐसा करना निहायत लाजमी है। हरियाणा-पंजाब का रीजन ऐसी है कि इन दोनों ने यह साबित कर दिया है कि हम बहुत कुछ पैदावार बढ़ा सकते हैं। अभी आप देखें। हमारा जो खेती का एरिया है, उसमें मुश्किल से 30 प्रतिशत के आस पास ऐरिये में सिंचाई होती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हरियाणा ने यह साबित कर दिया कि हम देश में दूसरों के मुकाबले बहुत आगे हैं। और पंजाब के बाद दूसरे नम्बर पर हैं। हालांकि हमारा एरिया पंजाब से छोटा है लेकिन हम फिर भी दूसरों से ज्यादा अनाज दे सकते हैं। अगर यहां पर भाक्ति ज्यादा दी जाए बिजली ज्यादा दी जाए, तो यह कुदरती बात है कि खेती के लिए ज्यादा पानी उपलब्ध होगा, और सिंचाई बढ़ जाएगी। हम रोज उपदेश देते हैं कि खेती की पैदावार ज्यादा करो। अगर किसी देश ने जिवित रहना है, किसी दूसरे देश के भिखारी नहीं बने रहना चाहते, तो यह लाजमी है कि वह पैदावार बढ़ाए। हम आजाद होने के बाद 20-22 साल में 5500 करोड़ का

अनाज बाहर से मंगवा चुके हैं। आप दूसरे सूबों की तरफ नजर डालें। वे सब डैफिसिट में हैं। हरियाणा की तरफ नजर डालें, पंजाबी की तरफ नजर डालें, हम वाकई सरप्लस हैं। हम अपनी जरूरत भी पूरी करते हैं और दे 1 को भी खिलाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर इन दोनों प्रदेशों को ज्यादा बिजली दी जाये जिससे कि सिंचाई ज्यादा हो सके तो हम अनाज का भण्डार करते हैं। उनमें दोनों सूबों ज्यादा अनाज दे सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर यहां पर एक एटॉमिक स्टेशन दे दिया जाए तो यह लाज्मी बात है कि उसका सदुपयोग होगा। यहां की जनता ने, यहां के किसान ने, यहां के उद्योगपतियों ने यह साबित कर दिया है— चाहे फरीदाबाद हो, चाहे बटाला हो, चाहे जालंधर हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे सोनीपत हो, कि हम मुल्क में दूसरे सूबों से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं चाहे वह उद्योग हो या खेती बाड़ी हो। आज यह जरूरी है कि गरीबी हटाई जाए और पैदावार ज्यादा की जाए। पैदावार ज्यादा वही कर सकता है जिसकी करने की क्षमता हो। जिसकी क्षमता है, उसको पूरे साधन नहीं दिये जाते। दे 1 में यह आवाज उठी है कि इन सूबों में खुहाली है इसलिए यहां पर नेक्लाईट मुवमेंट नहीं बन सकती। कई लोगों को यहा कि पंजाब और हरियाणा की खुहाली भी अखरती है। वैसे तो हर प्रांत यह चाहेगा कि उसके यहां एटॉमिक स्टेशन लगे लेकिन जैसा कि चौधरी राम लाल जी ने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो योजना भेजते हैं वह मंजूर हो जाती है। इसलिए यह भी हमारे चीफ मिनिस्टर का एक टैस्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर दबाने में, ऐजीटेशन दबाने में और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने यह कर दिया, वह कर दिया, मैं सर नहीं उठाने

दूंगा तो यह भी उनका एक टैस्ट होगा। एक कंस्ट्रक्टिव टैस्ट होगा, एक रचनात्मक टैस्ट होगा। दो तरीके से तरक्की होती है एक तो हमारे पास बिजली की कोई ज्यादा पैदावार नहीं है सिर्फ फरीदाबाद में थर्मल प्लांट है, पानीपत में अब लगने जा रहा है। यमुनानगर का पता नहीं क्या हुआ। इसी तरह पानी की हालत है। यमुना पर अभी तक डैम नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि आठ साल या छः साल में जमुना पर जो डैम चौधरी छोटूराम के जमाने से कागजों पर चलता आ रहा है अब तक हम भारत सरकार को नहीं मना पाए कि यह डैम बनना जरूरी है और तो तरक्की करने का कोई तरीका नहीं है या थर्मल प्लांट्स या जमुना पर डैम। परमाणु भाक्ति घर अगर लग जाए तो मैं समझता हूँ कि यह एक आधार बन जाएगा खुद गहरी का और हरियाणा देा को एक मार्ग दिखा सकेगा। जो लोग कहते थे कि हरियाणा जो है वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। यह छः सात जिलों का प्रान्त है यह क्या तरक्की करेगा। लेकिन इस प्रान्त ने यह साबित कर दिया कि देा समुद्धि में यह प्रान्त कितना फायदा कर सकता है। इन भावों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरजोर के साथ सरकार इस काम में यत्न करेगी।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त):स्पीकर साहब, समय तो थोड़ा है सिर्फ पांच छः मिनट बाकी है।

श्री अध्यक्ष: आप भुरु करें अगर टाइम कम होगा तो अगले दिन कन्टीन्यू होगा।

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिजली बहुत बड़ी भाक्ति है और किसी भी प्रदेा की, किसी

भी दे । की खु ।हाली और उसका विकास बिजली के उपर निर्भर करता है । इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हरियाणा प्रदे । एक कृशि प्रधान प्रदे । है और यदि इसको पूरा पानी और बिजली मिल जाए तो तो दे । के अन्न भंडार को भरने में यह बडा भारी सहयोग दे सकता है । अध्यक्ष महोदय, सब को पता हैकि जब हरियाणा प्रान्त अलग बना तो इस प्रदे । के अन्दर एक लाख टन अनाज का घाटा था और वह बाहर से मंगाना पडता था । आज हर प्रकार का अनाज मिलाकर 15-16 लाख टन हम दूसरे सूबो को भेजते है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर आज हमको पूरी बिजली मिल जाए, पूरा पानी मिल जाए तो, हरियाणा प्रदे । का किसान इतना मेहनती है कि वह बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकता है । यहां का उद्योगपति और यहां का मजदूर जो बहुत मेहनती है, वे भी हरियाणा की उन्नती में बडा योगदान दे सकते है । अध्यक्ष महोदय, अभी हम एक मिटिंग कर रहे थे । अभी पैडी सोइंग का सीजन चल रहा है, पर ट्यूबवैल को पूरी बिजली नहीं मिल रही । अगर आप दस घंटे प्रतिदिन बिजली दे दें तो हम बहुत ज्यादा धान की जीरी लगवा सकते हैं और उत्पादन बढा सकते है । उस मिटिंग में दोनो जिलों के एम0 एल0 ए0 भी मौजूद थे । हमने इस पर विचार किया । हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिजली हम दें लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिजली की भाक्ति हमारे पास बहुत कम है । आज जो विचार, जो भावनाएं मेरे साथियों ने व्यक्त की है वे बिल्कुल ठीक हैं । मैं मानता हूं कि आज अगर हमें पूरी बिजली मिल जाए तो हरियाणा प्रदे । प्रगति के मार्ग में इतना आगे बढ सकता है कि भायद कुछ दिनो में खु ।हाली के मामले में हिन्दुस्तान का एक नम्बर प्रदे । हो जाए बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि

हर दृष्टी से हरियाणा प्रथम दर्जे का प्रदेश हो सकता है। जहां तक परमाणु भाक्ति का प्रश्न है मैं दो चार मिनट में बतलाना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने कभी इस बात के लिए कसर नहीं रखी कि परमाणु भाक्ति घर हरियाणा में लगे। भारत सरकार को एप्रोच किया, आग्रह किया, उन पर दबाव डाला। भारत सरकार का जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है उसकी एक साइट सिलैक्ट इन कमेटी है। उस कमेटी के चेयरमैन 1970 में चंडीगढ़ आए और ताजे वाला के पास फ़ैजपूर के इलाके में साइट सिलैक्ट किया और भारत सरकार का जो जियोलोजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी उस साइट को एप्रूव कर दिया और भारत सरकार के उस विभाग ने हरियाणा सरकारसे जो टैक्नीकल डेटा, और जो इन्फॉर्मेशन मांगी वह तमाम हमने सप्लाई की और जिस प्रकार का सहयोग उन्होंने मांगा वह सहयोग हमने उनको तुरन्त दिया। इसके अलावा जिला गुडगांव में कोटला लेक के स्थान पर एक जगह और सिलैक्ट की गई और जियोलोजिकल डिपार्टमेंट ने उसकी भी एप्रूवैल दे दी यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब उसका फैसला होने लगा तो अक्टूबर 1972 में डिस्मिसन लिया गया कि यह परमाणु भाक्ति घर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नरौरा के स्थान पर लगाया जाये। मैं सदन को आपके द्वारा विचार वास दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार या बिजली बोर्ड ने किसी प्रकार की कोई कसर दबाव डालने में, आग्रह करने में उठा नहीं रखी। जो कुछ सहयोग उन्होंने मांगा वह उनको दिया गया।

स्पीकर साहब, अब स्थिति इस वक्त यह है कि तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर चार परमाणु भाक्ति घर हैं— एक तारापुर में बम्बई के पास, एक राणा प्रताप सागर राजस्थान में, एक कालापुर मद्रास में

और चौथा नारौरा यू० पी० में जो अण्डर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि एक और परमाणु भावित घर उत्तरी क्षेत्र(नार्दन जोन) में लगाया जाए। इसके लिए हम पूरी भावित के साथ लगे हुए हैं। पंजाब क्षेत्र भी इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन मुझे आशा कि एक किरण दिखाई देती है। भारत सरकार के परमाणु भावित विभाग ने यह कहा है कि जो-जो टैक्नीकल इंफरमैशन हरियाणा ने सप्लाई की थी उससे हम सैटिसफाइड हैं और हमने रिकार्ड पर यह तमाम चीजें रख ली हैं। जिस वक्त पांचवे परमाणु भावित घर के लगाने का फैसला होगा तो हरियाणा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और इस प्रस्ताव के प्रस्तावको को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से इसमें कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। हरियाणा के लिए इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है कि बिजली जैसी भावित का हमें केन्द्र मिल जाए। अब तो हिन्दुस्तान इस पोजीशन में है कि वह परमाणु ताप घर अधिक संख्या में लगा सके। अभी पिछले दिनों एक परमाणु विस्फोट भी भारत में हुआ है। जिससे हमारे पड़ोसी देशों भयभीत भी हो गया लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि यह भावित जो हमने अर्जित की है उस का प्रयोग देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए किया जाएगा। किसी पड़ोसी देश के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9:30 A.M. tomorrow.

13.00 बजे

(The sabha then adjourned till 9:30 A.M on Friday, the
12th July, 1974.)

अनुबन्ध-क

कृपया पृष्ठ (4)12 पर पद टिप्पणी देखिए

**Total number of class I, II, III & IV Government Employees
in the State**

***802. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state:-

(a) the total number of Class I, II, III & IV Government Employees in the State as on 31.3.1974; and

(b) the total of Class I, II, III & IV Government Employees out of those referred to in part(a) above, who belong to Scheduled Castes and Backward Classes, separately?

समाज कल्याण एवं कराधान मंत्री (श्री भयाम चन्द):

(क)	क्लास-I	क्लास-II	क्लास-III	क्लास-IV
	891	3230	100655	25373

(ख)

अनुसूचित जातियां				पिछड़े वर्ग कल्याण			
क्लास-I	क्लास-II	क्लास-III	क्लास-IV	क्लास-I	क्लास-II	क्लास-III	क्लास-IV
87	82	8457	6557	2	27	4585	2591